राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उत्तरांचल,उत्तराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रकाशित

सुरत–गुजरात,संस्करण शनिवार 01 जुलाई 2023 वर्ष–6,अंक–157 पृष्ठ–08 मूल्य–01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त

गिरने से बाल- बाल बचीं शिल्पा शेट्टी

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को हाल ही में टीवी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के सेट पर स्पॉट किया गया, जहां वह गिरने से बाल- बाल बचीं। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। अब शिल्पा का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिल्पा पिंक आउटफिट में नजर आ रही हैं। उन्होंने इंडो-वेस्टर्न साड़ी पहन रखी है, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन जैसे ही शिल्पा आगे बढ़ी, वह अपने कपड़े में फंस गईं, हालांकि शिल्पा के साथ उनकी टीम भी मौजूद थी, जिसने उन्हें गिरने से बचा लिया। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी वैनिटी वैन के सामने पैपराजी को पोज दिए। सोशल मीडिया पर फैंस ने वीडियो पर कमेंट की बौछार कर दी। वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अरे जरा संभल के'। वहीं कई लोग पैपराजी को ये वीडियो रिकॉर्ड करने पर खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, 'अरे ये गिरने का स्टाइल है'।

सर्व सेवा संघ भवन पर नहीं चला बुलडोजर

वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के सर्व सेवा संघ भवन पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले को लेकर संघ की याचिका पर अब हाईकोर्ट में तीन जुलाई को सुनवाई होगी। तब तक के लिए कोर्ट ने जिला प्रशासन को कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद समर्थकों ने सर्व सेवा संघ के गेट पर प्रदर्शन खत्म कर दिया है। वहीं, शनिवार को गांधी विचारकों के साथ कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि कल भी कार्यालय पर जुटेंगे और आगे की लड़ाई की रणनीति बनाएंगे। दरअसल, सर्व सेवा संघ भवन महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण और संत विनोबा की विरासत है। इस संगठन की स्थापना देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने इसे बचाने को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। वहीं, प्रियंका गांधी ने इसको लेकर कहा कि जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्रवाई के विरोध में सुबह 10 बजे शुरू से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन हुआ।

आंध्र प्रदेश : फार्मा फैक्ट्री में आग, 5 मरे

रिएक्टर में ब्लास्ट के बाद आग पूरी फैक्ट्री में फैली, 6 से ज्यादा कर्मचारी घायल

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में शुक्रवार को एक दवा की फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, 6 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए। न्यूज एजेंसी अठक के मुताबिक, आग अच्युतापुरम इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित सहिथी फार्मा में लगी। अनकापल्ली के रढ मुरली कृष्णा ने बताया

कि अच्युतापुरम इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित सहिथी फार्मा में एक रिएक्टर में ब्लास्ट के कारण आग लगी। इसमें कंपनी के 6 कर्मचारी घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर हैं। करीब 15 कर्मचारियों को दमकल की टीम ने बाहर निकाल लिया है। कंपनी के एक कर्मचारी ने बताया कि उसने ब्लास्ट की तेज आवाज सुनी। इसके बाद तुरंत ही आग लग गई और किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। सभी कर्मचारी घबराकर बाहर की ओर भागे। आग इतनी भीषण थी कि उसमें से उठता काला घना धुआं 5 किमी दूर से भी दिखाई दे रहा था। अनकापल्ली के एसपी मुरली कृष्णा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना कैसे हुई और इसमें प्रबंधन की कोई लापरवाही थी या नही, इसकी जांच की जाएगी। फायर ब्रिगेड की टीम से भी हादसे को लेकर जानिकारियां जुटाई जा रही हैं।

रांची खादगड़ा बस स्टैंड में आठ गाड़ियों में लगी आग

रांची । कांटाटोली खादगढ़ा बस स्टैंड में पहले पांच बस में आग लगी फिर लगभग एक घंटे की अंतराल के बाद तीन और बस में आग लगी। खादगड़ा एक के बाद एक आठ बस में भीषण आग लग गयी। आग इतनी भीषण थी की दूर- दूर तक लपटें दिखाई देने लगी। पहली घटना घटना दोपहर एक बजे के आसपास की बताई जा रही है। पांच बस में आग लगी जिस पर काबू पा लिया गया। इसके लगभग एक घंटे के बाद फिर तीन बस में आग लग गयी। निशांत ट्रेवलर्स, मां भवानी ट्रेवल्स, राधेश्याम और एलडी मोटर्स कंपनी की बसें आग की चपेट में आई हैं।

कन्हैयालाल हत्याकांड पर गहलोत झूठ बोलते हैं : अमित शाह

गहलोत का जवाब- गौस और रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया

उदयपुर। विधानसभा चुनाव अभियान को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को उदयपुर आए गृहमंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उदयपुर की जनसभा में गृह मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार तो कन्हैयालाल के हत्यारों को पकड़ना भी नहीं चाहती थी, उन्हें NIA ने पकड़ा। इस बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।

गहलोत ने कहा कि कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को राजस्थान पुलिस ने 4 घंटे के अंदर पकड़ लिया था। घटना 28 जून की थी, जबकि एनआईए को इस

मामले की जांच 2 जुलाई को सौंपी गई थी। गहलोत ने ट्वीट कर NIA को जांच सौंपने का ऑर्डर भी सार्वजनिक किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी गहलोत राजनीति कर रहे हैं। गहलोत हत्यारों को तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा और गहलोत झूठ बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। मैं डंके की चोट के साथ कहता हूं कि स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की होती तो हत्यारे फांसी पर लटक चुके होते। यही नहीं, जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों की सुनवाई के लिए गहलोत सरकार के एडवोकेट जनरल के पास समय नहीं है। हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता थे : गहलोत शाह के इस बयान पर गहलोत ने ट्वीट कर कहा- यह उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज उदयपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने जो किया वह एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है। गहलोत ने कहा कि ये दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्हें ये जांच करवानी चाहिए कि इन दोनों के मददगार कौन भाजपा नेता थे जो इनके लिए पुलिस थानों में फोन करते थे। एक ओपन एंड शट केस में चार्जशीट फाइल होने में भी इतना अधिक समय क्यों लगा और इन्हें अब तक सजा क्यों नहीं हुई?

प्रेमिका की बेवफाई पर युवक ने किया सुसाइड

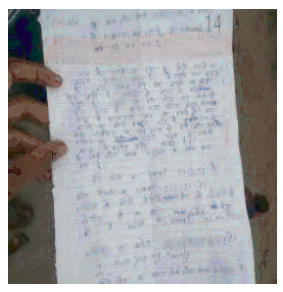

रायबरेली। एक युवक ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड कर लिया। फांसी के फंदे पर झूलते युवक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इस सुसाइड नोट में उसने अफेयर को लेकर तमाम बातें लिखी हैं। उसने प्रेमिका का नाम लिखते हुए लिखा, "मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जान दे रहा हूं। मैं तुम्हारी बेवफाई के चलते फांसी लगा रहा हूं।" सुसाइड नोट में युवक ने प्रेम संबंधों को साबित करने के लिए अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भी अंकित किया। वहीं प्रेमिका का नाम लिखते हुए उसका फोन नंबर भी लिख दिया। युवक की मौत के बाद उसके घर-परिवार में कोहराम मच गया। पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत संदिराम गांव का है। यहां गुरुवार को 26 साल के धीरज बौद्ध का शव फांसी के फंदे से उतारा गया। आत्महत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। वहीं धीरज के पास से मिले सुसाइड नोट में प्रेमिका के बारे में तमाम बातें लिखी मिलीं। धीरज ने सुसाइड नोट में लिखा, "मैं सिर्फ और सिर्फ अर्चना (बदला हुआ नाम) की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। इसमें मेरे घर वालों का कोई लेना देना नहीं है। आज मैं मरने जा रहा हूं। मेरे मरने का कारण अर्चना है। मैं उससे प्यार करता हूं, इसमें मेरे घर वालों का कोई दोष नहीं है। मैं अर्चना की वजह से ही मरने जा रहा हूं। उससे मेरी हर रोज बात होती थी और आज उसने मुझे बहुत उल्टा-सीधा बोला। अब मैं मरने जा रहा हूं।"

मणिपुर के सीएम बोले- इस्तीफा नहीं दे रहा

3 बजे राजभवन जाने वाले थे, हजारों महिला समर्थकों के प्रदर्शन के बाद फैसला बदला

मणिपुर । 3 मई से जारी हिंसा के बीच शुक्रवार सुबह से इस बात की चर्चा रही कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ने वाले हैं। वे दोपहर 3 बजे राज्यपाल अनुसुइया उइके से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। हालांकि, अटकलों के बीच सैकड़ों महिलाएं इंफाल में राजभवन के सामने पहुंचीं। महिलाओं ने मांग की कि बीरेन सिंह इस्तीफा ना दें, बल्कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। शाम 4 बजकर 1 मिनट पर एन बीरेन सिंह ने एक ट्वीट किया और लिखा- इस मोड़ पर तो मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूं। यानी बीरेन सिंह ने साफ कर दिया कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक वरिष्ठ मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन जनता के दबाव में उन्होंने अपना मन बदल लिया। बीरेन सिंह गवर्नर हाउस के लिए निकल रहे थे, लेकिन अपने घर के बाहर समर्थकों के प्रदर्शन को देखने के बाद वे वापस लौट गए। बीरेन सिंह के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने ह्यूमन चेन बनाया और कहा कि वे नहीं चाहती कि उनके सीएम इस्तीफा दें। उनके इस्तीफे की एक कॉपी भी तब फाड़ दी गई, जब दो मंत्री इसे लेकर सीएम हाउस के बाहर आए और उसे प्रदर्शन कर रही महिलाओं को सौंपा। इससे पहले मणिपुर के स्थानीय लोगों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि उट इस्तीफा दें, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वह हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम सीएम को समर्थन दे रहे हैं। हम 2 महीने से उथल-पुथल की स्थिति में हैं। लोगों ने कहा कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भारत सरकार और मणिपुर सरकार इस संघर्ष को लोकतांत्रिक तरीके से हल करेगी। ऐसी स्थिति में अगर मणिपुर के CM इस्तीफा दे देते हैं, तो लोग यहां कैसे रहेंगे। हमारा नेतृत्व कौन करेगा। मणिपुर में गुरुवार को हुई गोलीबारी में 3 लोगों की जान चली गई। हिंसा की 2 घटनाओं में से एक गुरुवार सुबह 5:30 बजे कांगपोकपी जिले में हुई। यहां हथियार बंद लोगों ने गोलीबारी की। इस घटना में 2 लोगों की जान गई थी। लोगों ने शवों को लेकर उट हाउस तक जुलूस निकालने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया था। इसके अलावा, गुरुवार शाम को ही हिंसा की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। हिंसा में अब तक 131 से ज्यदा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 419 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

गुजरात: आफत बनकर आई बारिश

200 मिमी बरसे बादल, नौ लोगों की गई जान

अहमदाबाद। गुजरात के विभिन्न इलाकों में पिछले 30 घंटो से भारी बारिश हो रही है। इस दौरान राज्य में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने गुजरात के विभिन्न जिलों में शनिवार को भी भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इसके अलावा रविवार और सोमवार को हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। जूनागढ़, जामनगर, मोर्बी, कच्छ, सूरत, और तापी जिलों में दिन में भारी बारिश होने के कारण सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई शहरों और इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में शुक्रवार की सुबह भारी बारिश के कारण सड़को को बंद कर दिया गया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य के 37 तालुकों में शुक्रावार रात 12 बजे तक 100 मिमी तक बारिश दर्ज की जाएगी। तापी जिले के व्यारा तालुका में 30 घंटों में 299 मिमी तक वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा जामनगर में 298 मिमी, तापी के वालोड तालुका में 288 मिमी, सूरत के महुवा में 256 मिमी, जामनगर शहर में 236 मिमी, सूरत का बारडोली में 223 मिमी, जूनागढ़ के मेंदर्दा में 207 मिमी और तापी जिले के डोलवन में 206 मिमी तक बारिश हुई है।

केंद्र सरकार के 42 लाख सीजीएचएस लाभार्थियों को बड़ी राहत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 42 लाख कर्मचारी व उनके परिजन, जो सीजीएचएस के दायरे में आते हैं, उनके लिए राहत की खबर है। अब उन्हें टेस्ट के लिए ज्यादा रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विभिन्न तरह के 36 टेस्ट के रेट निर्धारित किए हैं। ये टेस्ट नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) और नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त किसी भी लैब में कराए जा

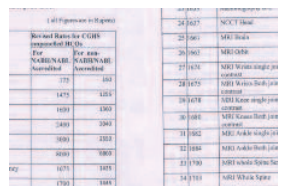

सकते हैं। अगर किसी 'सीजीएचएस' लाभार्थी के लिए एनएबीएल/एनएबीएच लैब में जाना संभव नहीं है, तो उनके लिए गैर मान्यता प्राप्त लैब के रेट तय किए गए हैं। सीजीएचएस निदेशालय द्वारा हाल ही में जारी कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, अगर कोई लाभार्थी एनएबीएल/एनएबीएच से मान्यता प्राप्त लैब पर ईसीजी कराता है तो उसे 175 रुपये देने पड़ेंगे। यही टेस्ट गैर मान्यता प्राप्त लैब पर 150 रुपये में होगा। मान्यता प्राप्त लैब में इको टेस्ट 1475 रुपये में, जबकि गैर मान्यता प्राप्त लैब में इसके लिए 1255 रुपये देने होंगे। मान्यता प्राप्त लैब में फेटल इको टेस्ट 1600 रुपये में होगा। गैर मान्यता प्राप्त लैब में ये टेस्ट 1360 रुपयों में होगा। स्ट्रेस इको टेस्ट के लिए मान्यता प्राप्त लैब में 2400 रुपये, जबकि गैर मान्यता प्राप्त लैब में 2040 रुपये लगेंगे।

वायुसेना में तेजस के सात साल पूरे, रक्षा मंत्रालय ने कहा- यह भविष्य में बनेगा भारतीय वायुसेना की ताकत

नई दिल्ली। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने कई बार अलग-अलग देशों में युद्धाभ्यास करते हुए अपनी ताकत को जाहिर कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय वायु सेना को अगले साल फरवरी से हल्के लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए की डिलीवरी मिलने की उम्मीद है। तेजस का नया संस्करण में सीमा पार मिसाइलों के साथ कई हथियारों को दागने में सक्षम होगा। तेजस ने भारतीय वायुसेना में सेवा में सात साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भविष्य में तेजस विमान के नए संस्करण भारतीय वायुसेना की ताकत बनेंगे। मंत्रालय ने पिछले साल भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस एमके-1ए जेट की खरीद के लिए भारत की एयरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपये का सौदा किया था। तेजस विमान खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाने वाले देशों में मिस्र, अर्जेंटीना, अमेरिका,

ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस शामिल हैं। शनिवार को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) वायुसेना में अपनी सेवा के सात साल पूरे कर लेगा। तेजस एक एकल इंजन वाला बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है जो बड़े खतरे वाले वायु वातावरण में काम करने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एलसीए एमके-1ए में आधुनिक सेंसर, रडार सिस्टम, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक उपरकरण लगाए गए हैं। तेजस का नया संस्करण लंबी दूरी से टारगेट को दागने में सक्षम होगा। इनमें से कई हथियार स्वदेशी मूल के होंगे। बयान में कहा गया है कि विमान की डिलीवरी फरवरी 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। तेजस को हवा में रक्षा, समुद्री में निगरानी और हमले में भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। तेजस ने अपनी पहली उड़ान जनवरी 2001 में भरी थी। इसके बाद साल 2016 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तेजस की खासियत के बारे में बात करें तो तेजस विमान यह आठ से नौ टन लोड लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। तेजस सुखोई फाइटर जेट के बराबर हथियार और मिसाइल ले जा सकता है, जबकि सुखोई का वजन तेजस के मुकाबले काफी कम है।

संपादकीय

कनाडा को संदेश

अलगाववाद के विरुद्ध भारत की नई वैश्विक आक्रामकता न केवल सुखद, बल्कि अनुकरणीय भी है। यह बात छिपी नहीं है कि कनाडा इन दिनों खालिस्तानी अलगाववादियों का अड्डा बना हुआ है और वहां से लगातार भारत को परेशान करने की साजिशें हो रही हैं। ऐसी साजिशों पर हमला बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि कनाडा की सभी प्रतिक्रियाएं वास्तव में वोट-बैंक की मजबूरियों के कारण बाधित रही हैं। अगर कनाडा की मंजूरी से ऐसी गतिविधियां चलती रहती हैं, जो हमारी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा पर आघात करती हैं, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। यह कनाडा को दिया गया अब तक का सबसे तीखा संदेश है। भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वह कनाडा की उदासीनता के सामने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। वैसे यह देखने वाली बात है कि कनाडा सरकार भारत की चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में, दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी तय है। ऐसे एकाधिक दुखद प्रकरण हैं, जिनसे भारत का विदेश मंत्रालय रुष्ट है। कनाडा ने अभी तक भारत को यह आश्वासन नहीं दिया है कि वह अपने यहां भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के प्रयास करेगा। दरअसल, सिखों की बढ़ती संख्या राजनीतिक रूप से कनाडा में महत्वपूर्ण होती जा रही है। वहां की सरकार या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को सिखों का समर्थन चाहिए। सिखों का समर्थन करके अपने लिए सियासी ताकत तलाश रहे नेताओं को भारत-कनाडा संबंधों की चिंता नहीं है। भारत वर्षों पहले सिख आतंकवाद की समस्या का समाधान कर चुका है, लेकिन उसे अगर कनाडा की स्थानीय राजनीति परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है, तो भारत की नाराजगी स्वाभाविक है। भारतीय विदेश मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन समय आ गया है कि कनाडा को सही पटरी पर लाने के लिए जुबानी जमाखर्च से आगे बढ़कर ठोस उपाय किए जाएं। उन विकल्पों पर विचार करना होगा, जो कूटनीतिक दृष्टि से कारगर हैं। कम से कम तीन अहम देश ऐसे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जहां चंद खालिस्तानियों ने अपनी संकीर्ण मानसिकता के झंडे अपने माल-गोदाम से फिर निकाल लिए हैं। सिखों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो अलगाववाद की ओर नहीं जाना चाहता, जो अमन पसंद है और अपने पंथ की स्नेहिल बुनियाद को समझता है। मेल-मिलाप का पैरोकार पंथ अलगाववाद के बड़े घाव अतीत में झेल चुका है और यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसी को गलत राह पर न जाने दे। संकीर्ण खालिस्तानी, जो कभी पंजाब लौटना नहीं चाहेंगे, वे भी अलगाववाद की बुझी हुई आग को दोबारा सुलगाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की सरकारें अपेक्षाकृत सजग हैं, लेकिन कनाडा सरकार खुद अपना मजाक उड़वाने की तैयारी में है। सच्चाई से परे जाकर आखिर किस आधार पर कनाडा अलगाववाद को सही ठहरा सकता है, उच्च स्तर पर भारत सरकार को उससे बात करनी चाहिए। अभी 4 जून को कनाडा में एक जगह झांकी प्रदर्शित की गई, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया। ऐसा जश्न मनाने वालों की जितनी निंदा की जाए, कम होगी। ऐसे जश्न का बचाव किसी भी सांविधानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पैमाने पर नहीं किया जा सकता। तब भी भारतीय विदेश मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अब विदेश मंत्रालय को कुछ आक्रामक होना ही पड़ेगा, ताकि कनाडा की राजनीति को गलत दिशा में जाने से रोका जा सके।

आज का राशीफल

मेष शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। किसी रिश्तेदार के आगमन से मन प्रसन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा।

वृषभ पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खान-पान में संतुलन बना कर रखें। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।

मिथुन दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आय के नये स्त्रोत बनेंगे। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी अपेक्षित है।

कर्क पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। धन लाभ होगा।

सिंह रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कन्या पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा।

तुला आर्थिक योजना सफल होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

वृश्चिक पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग रहेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

धनु जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। फिजूलखर्ची से बचें अन्यथा कर्ज की स्थिति आ सकती है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन हानि की संभावना है।

मकर दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

कुम्भ गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। खान पान में संयम रखें। स्वास्थ्य शिथिल रहेगा। आमोद प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी।

मीन पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। नेत्र विकार की संभावना है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

दिल भी मिले तो बने बात

(लेखक - रमेश सर्राफ धमोरा)

बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के प्रयासों से पटना में 15 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात कही। बैठक में शामिल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त है। जबकि जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना(उद्धव), झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, द्रुमक, भाकपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भाकपा (माले), अपने-अपने प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है। पटना की बैठक में शामिल 15 दलों की देश के 11 प्रदेशों में सरकार चल रही है। पिछले 9 सालों में पहली बार 15 राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर बैठकर चर्चा की है। जो देश की राजनीति के लिए आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण घटना साबित होगी। पटना में जुटे 15 दलों के लोकसभा में 142 सांसद हैं। जो कुल लोकसभा सदस्यों का 26 प्रतिशत होता है। वही राज्यसभा में इन दलों के पास 94 सांसद है जो 38 प्रतिशत है। राज्यों की विधानसभाओं की कुल 4123 सीटों में से 1717 विधानसभा सीटें इन 15 दलों के पास है जो कुल विधानसभा सदस्यों का 42 प्रतिशत होता है। विपक्षी दलों की पटना बैठक में शामिल हुए दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की देश के चार प्रदेशों राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में सरकार चल रही है। कांग्रेस के पास लोकसभा में 49 राज्यसभा में 29 व विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में 725 सदस्य है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल 11 करोड़ 94 लाख 95 हजार 214 वोट मिले थे। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को नेता प्रोजेक्ट किया जाये। राजद नेता लालू यादव व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं। वही ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं। पटना मीटिंग में शामिल हुए नेताओं के हाथ तो जरूर मिले मगर अभी तक दिल नहीं मिल पाये हैं। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लाये गये अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस को उनका समर्थन करने की बात कही। जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे व अरविंद केजरीवाल में बहस भी हुई। मलिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी के मंच पर इस बाबत चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्यसभा में कांग्रेस उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मतदान नहीं करेगी तो भविष्य में वह किसी भी विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर नाराजगी जताई। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए लगातार आंदोलन कर सरकार की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस को अपने प्रादेशिक नेताओं को उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से रोकना होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में माकपा व भाकपा भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ सक्रिय है।

राजद नेता लालू यादव व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं। वही ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं। पटना मीटिंग में शामिल हुए नेताओं के हाथ तो जरूर मिले मगर अभी तक दिल नहीं मिल पाये हैं। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लाये गये अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस को उनका समर्थन करने की बात कही। जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे व अरविंद केजरीवाल में बहस भी हुई। मलिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते हैं।

पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस, माकपा व भाकपा ने मिलकर लड़ा था। उसके बावजूद उनका खाता भी नहीं खुल सका था। इससे तीन दलों के नेताओं को ममता बनर्जी से खासी नाराजगी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की सरकार को हटाकर सत्ता में आई थी। कभी वामपंथ का गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में आज वामपंथी दलों का एक भी विधायक या सांसद नहीं है। इसके लिए वामपंथी दलों के नेता ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ लगातार हमलावर रहते हैं। जम्मू कश्मीर में कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक दूसरे की जानी दुश्मन होती थी। मगर दोनों ही दल अब सत्ता से बाहर है। इसलिए आपस में हाथ मिला रहे हैं। पीडीपी के पास तो एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीपी का एक भी सांसद नहीं जीता था। जम्मू-कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने घोषणा कर रखी है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वह चुनाव नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर काम कर रही है। बिहार में जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा व भाकपा की मिली जुली सरकार चल रही है। बिहार सरकार में शामिल हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने पटना बैठक से एक दिन पूर्व बिहार सरकार से अलग होकर अपनी पार्टी का समर्थन वापस ले लिया। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक झटके से कम नहीं था। वह एक तरफ तो विपक्षी दलों को एक करने में लगे हैं। वहीं उनकी सरकार में शामिल पार्टी उनको छोड़कर भाजपा नीत एनडीए में शामिल हो जाती है। इससे नीतीश कुमार की मुहिम कमजोर पड़ती है।

पटना बैठक में बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, अन्ना द्रुमक, तुलुगु देशम पार्टी, अकाली दल, जनता दल सेक्यूलर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन, आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मुस्लिम लीग सहित बहुत से ऐसे छोटे राजनीतिक दल जो कांग्रेस व भाजपा से समान दूरी रखकर चल रहे हैं। उनके नेता भी बैठक में शामिल नहीं हुये। इससे लगता है कि नीतीश कुमार की मुहिम अभी अधूरी है। जब तक भाजपा विरोधी छोटे-बड़े सभी राजनीतिक दल एक साझा मंच पर एकत्रित नहीं होंगे तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाना संभव नहीं होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अगले लोकसभा चुनाव में कई प्रदेशों में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कही है। ओडिशा में बीजू जनता दल, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का आज भी पूरा प्रभाव नजर आ रहा है। ऐसे में 15 दलों का यह गठबंधन कैसे मुकाबला कर पाएगा। चुनाव में भाजपा के साथ इनको अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों का भी मुकाबला करने पड़ेगा। जिससे विपक्ष की एकता कमजोर होगी। पटना की मीटिंग में जिस तरह से नेताओं ने हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवाई है। यदि उसी तरह से उनके दिल भी मिल जाये तभी विपक्षी एकता सार्थक होगी। वरना तो भाजपा को हरा पाना मुश्किल ही होगा। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने करीबन 23 करोड़ वोट लेकर 303 सीटे जीती थी। वहीं इन 15 दलों ने भी उतने ही वोट लेकर 142 सीट ही जीत पाये थे। बराबर वोट लेकर भी आधी से भी कम सीटे जीतने का मुख्य कारण था विपक्षी वोटो का आपस में ही लड़कर बिखर जाना। इसी लिये विपक्षी वोटो का संगठित होना बहुत जरूरी है। विपक्षी दलों की एकता कितनी सिरे चढ़ पाती है। इस बात का पता तो चुनावों में ही चल पायेगा। (लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार है। इनके लेख देश के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं।)

चिकित्सकों की है मानव जीवन में अहम भूमिका

(लेखिका - श्वेता गोयल/ईएमएस)

(राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (1 जुलाई) पर विशेष)

भारत में प्रतिवर्ष एक जुलाई को डॉक्टरों के समर्पण और ईमानदारी के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए 'राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस' मनाया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा यह दिवस सबसे पहले वर्ष 1991 में मनाया था। भारत में जहां प्रतिवर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, वहीं कई दूसरे देशों में भी डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए अलग-अलग तारीखों पर यह दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में पहली बार मार्च 1933 में डॉक्टर्स डे मनाया गया था। यह दिन चिकित्सकों को कार्ड भेजकर तथा मृत डॉक्टरों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर मनाया जाता था। अमेरिका में यह दिवस 30 मार्च को, ईरान में 23 अगस्त को तथा क्यूबा में 3 दिसम्बर को मनाया जाता है। भारत में हर साल एक जुलाई को ही यह दिवस मनाए जाने का विशेष कारण है। दरअसल देश के जाने-माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डा. बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि एक जुलाई को ही है और उन्हें श्रद्धांजलि एवं सम्मान देने के लिए ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के लिए यही दिन निर्धारित किया गया। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना जिले में हुआ था तथा निधन 1 जुलाई 1962 को हुआ। डा. बिधान चंद्र ने अपने जीवनकाल में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने वर्ष 1911 में अपने चिकित्सकीय कैरियर की शुरुआत की और एक बेहतरीन डॉक्टर होने के साथ ही वे भारत की आजादी के आन्दोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी रहे।

उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट बार्थोलोम्यू अस्पताल से डॉक्टरी की पढ़ाई की कोशिश की लेकिन तब उनके भारतीय होने के कारण उन्हें वहां दाखिला नहीं मिला। बिधानचंद्र भी अपनी धुन के पक्के और दृढ़निश्चयी थे, उन्होंने हार नहीं मानी और दाखिले के लिए करीब डेढ़ माह तक लगातार अस्पताल के डीन के पास आवेदन करते रहे। अंततः उनके दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर डीन ने 30वीं बार में उनका आवेदन स्वीकार कर लिया और अपनी लग्न तथा कड़ी मेहनत से उन्होंने मात्र सवा दो साल में ही डिग्री हासिल कर एक साथ फिजिशयन तथा सर्जन की रॉयल कॉलेज की सदस्यता हासिल की। वहां से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वदेश लौटकर उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कार्यों को अंजाम दिया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें 'बंगाल का आर्किटेक्ट' भी कहा जाता है। वर्ष 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजे गए डा. बिधान चंद्र की याद में ही तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा 1991 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तभी से हर साल एक जुलाई को ही यह दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा किया जाता है।

हमारे समाज में तो डॉक्टरों को भगवान के समान यूं ही नहीं माना गया है। कोरोना महामारी से देश को उबारने में तो हमारे डॉक्टरों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ऐसे कठिन समय के दौरान डॉक्टर तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिस प्रकार दिन-रात कोविड मरीजों की देखभाल में जुटे रहे, उसके लिए पूरा समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। दरअसल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के दौरान तो डॉक्टर फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में सामने आए थे। महामारी के उस भयानक दौर में देवदूत बनकर लाखों लोगों का जीवन बचाने में डॉक्टरों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोरोना काल में बहुत से डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को नया जीवन प्रदान किया था। उस दौरान मरीजों की जान बचाते-बचाते प्राणघातक कोरोना वायरस के कारण सैंकड़ों डॉक्टरों की मौत भी हुई थी लेकिन फिर भी डॉक्टर पूरी दुनिया को कोरोना महामारी से उबारने में जुटे नजर आए थे। डॉक्टरों की ही बदौलत महामारी के उस भयावह दौर में करोड़ों लोगों का जीवन बचाया जा सका था।

सामान्य दिनों में भी डॉक्टर लोगों को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से निजात दिलाने में पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे में चिकित्सक दिवस हमें स्मरण कराता है कि डॉक्टरों की हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका रहती है। कई बार कुछ गंभीर मरीजों के मामलों में लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर सफल नहीं हो पाते और ऐसे कुछ अवसरों पर बिना उनकी किसी गलती के उन्हें ऐसे मरीज के परिजनों का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। हालांकि ऐसे अधिकांश मामलों में मरीज की हालत ही इतनी गंभीर होती है कि डॉक्टर चाहकर भी मरीज के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। स्विटजरलैण्ड के प्रख्यात मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक कार्ल गुस्ताव जंग ने एक बार कहा था कि दवाईयां बीमारियों का इलाज करती हैं लेकिन मरीजों को केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। उनका यह उद्धरण मौजूदा समय में तो सर्वाधिक प्रासंगिक नजर आता है। किसी भी मरीज की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उसके इलाज के लिए उपयुक्त दवाओं का चयन डॉक्टर ही करता है। कनाडा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर विलियम ऑस्लर ने कहा था कि एक अच्छा डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है जबकि महान् डॉक्टर उस मरीज का इलाज करता है, जिसे बीमारी है।

(लेखिका शिक्षिका तथा स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

डिजिटल और ऑनलाइन के नाम पर अरबों-खरबों का घोटाला

(लेखक-सनत कुमार जैन)

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इन दिनों डिजिटल और ऑनलाइन सेवाओं का बहुत बड़ा प्रचार-प्रसार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, कि उन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले घपले खत्म कर दिए हैं। हितग्राहियों को सीधे केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता भेजी जा रही है। जो भी टेंडर हो रहे हैं, वह सब डिजिटल ऑनलाइन तौर तरीके से बुलाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार रिश्वत और घोटाले पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। लेकिन जो जानकारी निकलकर अब बाहर सामने आ रही है। उसके अनुसार पिछले वर्षों में करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले, डिस्टलाइजेशन और ऑनलाइन लेनदेन के कारण बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में बोगस राशन कार्ड धड़ल्ले से चल रहे हैं राशन वितरण में भी राशन दुकानदार एवं शासकीय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर बड़े-बड़े घोटाले कर रहे हैं हितग्राहियों को जो सहायता केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही है उनमें भी सरकारी अमला मनमाफिक फर्जी बैंक खातों के नंबर डालकर सही हितग्राहियों और सरकार के खजाने में डाका डाल रहे हैं वही गबन और घोटाले के नए-नए तरीके शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों ने खोज लिए हैं इसमें राजनेताओं का भी संरक्षण देखने को मिल रहा है। जमीनों का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर घपले और घोटाले शुरू हो गए हैं। जो अरबों रुपए के घोटाले हैं। शासकीय और आदिवासियों की जमीन मैं गलत प्रविष्टि करके धोखेबाज, घोटालेबाज बड़े-बड़े घोटाले कर रहे हैं, इसको पकड़ पाना भी बहुत आसान नहीं होता है। जब यह पकड़े जाते हैं, तब तक बडी देर हो चुकी होती है। मामला कानूनी दांव पेंच में फंस जाते हैं। अरबों रुपए के घोटाले देखते ही देखते हो जाते हैं मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के हितग्राहियों के खाते में जो रकम भेजी जाती है उसमें भी बड़े पैमाने पर हर जिले में बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं। जिंदा व्यक्ति को मृत बता दिया जाता है। मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता है। घोटाले ऑडिट के दौरान अब सामने आ रहे हैं। सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वह भी डिजिटल और ऑनलाइन तरीके से मनमाने तरीके से शासकीय खजाने को बड़े पैमाने पर घपले घोटालों के किस्से समाचार पत्रों में अब बड़े आम हो चले हैं जब तक अधिकारियों और कर्मचारियों को त्वरित रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। उन्हें जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा तब तक डिजिटल और ऑनलाइन घोटालों को रोक पाना सरकार के लिये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का उल्लेख कई सार्वजनिक सभाओं में कर चुके हैं। राजीव गांधी के राज में बड़ा भ्रष्टाचार होता था। राजीव गांधी का कहना था, कि केंद्र से जो पैसा राज्यों को भेजा जाता है उसका मात्र 15 फ़ीसदी ही उपयोग में लाया जाता है। बाकी भ्रष्टाचार और अन्य कार्यों में खर्च हो जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय ना तो कंप्यूटर थे, ना ही ऑनलाइन लेन-देन होता था। अब कंप्यूटर भी हैं डिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, ऑनलाइन लेन-देन भी हो रहा है। इस स्थिति में यदि अरबों खरबों रुपए की धोखाधड़ी, गबन और रिश्वत का खेल चल रहा है। यह स्थिति अभी भी नहीं रुक पा रही है तो भगवान ही इन गडबडियों को रोक सकता है। सरकार के वश में अब यह भी नहीं रहा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया एक पैसे की बढ़त के साथ ही 82.04 पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया शुक्रवार को शुरूआती कारोबार में 82.02 प्रति डॉलर पर लगभग स्थिर रहा। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती के बीच रुपए में स्थिरता रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया गिरावट के साथ 82.05 पर कमजोर खुला। बाद में यह 82.01 ये 82.07 प्रति डॉलर के दायरे में रहा। शुरुआत में रुपया बुधवार को बंद स्तर से मात्र एक पैसे की बढ़त के साथ 82.02 प्रति डॉलर रहा। मुद्रा बाजार गुरुवार को बकरीद के मौके पर बंद था। वहीं छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को बताते वाला डॉलर सूचकांक 0.06 फीसदी की गिरावट के साथ 103.28 रहा।

बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 295.72 लाख करोड़ पहुंचा

नई दिल्ली । शेयर बाजार में बढ़ोतरी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण शुक्रवार को शुरूआती कारोबार में रिकॉर्ड 295.72 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 499.42 अंक की बढ़त के साथ अबतक के उच्चतम स्तर 64,414.84 अंक पर रहा। शेयरों में तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण उछलकर 2,95,72,338.05 करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे पहले 21 जून को बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,94,36,594.50 करोड़ रुपये पहुंचा था। सेंसेक्स शेयरों में पावर ग्रिड, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक और टाइटन प्रमुख रूप से लाभ में रहें।

शाओमी ने भारत में शुरू की छंटनी

नई दिल्ली । स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी इंडिया को भारत के बाजार में हिस्सेदारी कम होने की चुनौती से जूझना पड़ रहा है और साथ ही सरकारी एजेंसियों की सख्ती का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कंपनी ने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाओमी इंडिया अपने कारोबारी ढांचे में बदलाव कर रही है। इसके तहत कंपनी अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। कंपनी की योजना कर्मचारियों की संख्या 1 हजार से नीचे लाने की है। इस साल की शुरुआत में कंपनी के 1400-1500 कर्मचारी थे। इससे पहले पिछले हफ्ते कंपनी ने 30 कर्मचारियों की छुट्टी की थी और अब धीरे-धीरे कुल कर्मचारियों की संख्या 1 हजार से नीचे लाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि मार्केट शेयर में गिरावट और सरकारी एजेंसियों की सघन जांच के चलते यह छंटनी हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि रीस्ट्रक्चरिंग के चलते अधिकतर फैसले लेने का अधिकार शाओमी इंडिया की चाइनीज पैरेंट कंपनी शाओमी के पास चला गया है और इस साल की शुरुआत से यह कर्मचारी घटा रही है। हालांकि शाओमी इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय इकाई के पास पूरा अधिकार है और कर्मचारी कितने होंगे, यह कारोबार के हिसाब से तय होता है। प्रवक्ता ने कहा कि जब और जैसी भी जरूरत होगी, हायरिंग भी जारी रहेगी।

शेयर बाजार भारी उछाल के साथ बंद

सेंसेक्स 803 , निफ्टी 216 अंक ऊपर आया

मुम्बई ।

शेयर बाजार शुक्रवार को भारी उछाल पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबार दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही लिवाली (खरीददारी) हावी होने से बाजार ऊपर आया। दिन भर के कारोबार के बाद बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 803.14 अंक करीब 1.26 फीसदी बढ़कर 64,718.56 अंक पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 216.95 अंक तकरीबन 1.14 फीसदी ऊपर आकर 19,189.05 अंक पर बंद हुआ। आज के कारोबार के दौरान सेंसेक्स के शेयरों में से 28 शेयर लाभ के साथ ही हरे निशान पर बंद हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, के शेयर सबसे अधिक लाभ के साथ ही 4.14 फीसदी ऊपर आये। इसके अलावाइंफोसिस, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा और टीसीएस सेंसेक्स के सबसे अधिक लाभ वाले पांच शेयर रहे। वहीं सेंसेक्स के शेयरों में से केवल 2 शेयर ही नुकसान के साथ ही लाल निशान पर बंद हुए। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर सबसे अधिक 0.33 फीसदी तक गिरे। इसके अलावा केवल एनटीपीसी के शेयर में ही गिरावट रही। इससे पहले आज सुबह बाजार तेजी के साथ खुला। सुबह निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर

पर कारोबार कर रहे थे। सुबह निफ्टी 130 अंक की बढ़त के साथ 19105 के आसपास दिख रहा था। वहीं सेंसेक्स 478.39 अंक की बढ़त के साथ 64,393.81 पर कारोबार कर रहा था। वहीं अमेरिकी बाजारों में भी मिलाजुला रुख रहा। डाओ जोंस, एसएंडपी 500 सूचकांक 0.8 प्रतिशत तक बढ़े, जबकि नेस्डेक कंपोजिट सूचकांक में कोई बदलाव नहीं हुआ। शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में एशिया-प्रशांत बाजारों में भी मिलाजुला रुख रहा। निक्कई 225 में 0.1 फीसदी की बढ़त हुई, जबकि कोस्पी, हांग कांग और एसएंडपी 200 सूचकांक एक फीसदी तक गिर गए।

गो फर्स्ट की उड़ानें 6 जुलाई तक रद्द

मुंबई । वित्तीय संकट का सामना कर रही गो फर्स्ट एयरलाइन ने अपनी उड़ानें अब 6 जुलाई तक रद्द कर दी है। कंपनी की तरफ से इस बारे में घोषणा की गई। एयरलाइन की तरफ से उड़ानें रद्द करने की समयसीमा एक के बाद एक लगातार बढ़ाई जा रही है। दिवाला समाधान प्रक्रिया का सामना कर रही एयरलाइन में उड़ानों का परिचालन 3 मई से बंद है। तब से उड़ानें रद्द होने की अवधि कई बार बढ़ाई जा चुकी है। गो फर्स्ट के मौजूदा मैनेजमेंट के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारियों के साथ कंपनी की पुनरुद्धार के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। कंपनी ने ट्वीट किया कि परिचालन संबंधी कारणों से 6 जुलाई तक प्रस्तावित गो फर्स्ट की उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन की बहाली के लिए आवेदन किया हुआ है। कंपनी ने कहा है कि हम टिकट बुकिंग जल्द बहाल करने में सफल होंगे। इससे पहले सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार डीजीसीए रि वाइल प्लान से जुड़े गो फर्स्ट के दस्तावेजों की जांच करेगा। ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की अनुमति देने से पहले तैयारियों पर एक ऑडिट करेगा।

सभी को जरूरी नहीं पैन से आधार को लिंक करना

नई दिल्ली ।

पैन कार्ड-आधार को लिंक करने के लिए आयकर विभाग ने 30 जून तक का समय दिया है। यदि कोई व्यक्ति 30 जून तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग इस तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक करेंगे उन्हें पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। हालांकि पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता के बावजूद देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है। इन लोगों का आधार पैन से लिंक न होने के बावजूद इनऑपरेटिव नहीं होगा, अगर ये लोग पैन को आधार से लिंक भी करना चाहे तो इन्हें पेनाल्टी भी नहीं देगी होगी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139एए के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 30 जून की समय सीमा के भीतर अपने आधार को पैन के साथ लिंक करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हो पाता हो तो व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आप 30 जून तक लिंक नहीं करते तो 1 जुलाई से आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। यानी कि अगर इनऑपरेटिव हो चुके पैन को दोबारा एक्टिव कराते हैं तो 1000 रुपए की फीस भरनी होगी। इन लोगों को मिलेगी छूट- असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों को, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय, कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था और ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

टमाटर के बाद अब प्याज ने निकाले आखों से आंसू, कीमतों में हुई बढ़ोतरी

(एजेंसी)

देश में टमाटर की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद अब प्याज के भाव ने भी आसमान छूना शुरू कर दिया है। पिछले 4 दिनों के अंदर प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। 15 रुपए किलो बिकने वाले प्याज की कीमत अब 20 से 25 रुपए हो गई है। इस तरह प्याज भी पिछले 4 दिनों में 10 रुपए महंगा हो गया है।

अगर प्याज के होलसेल रेट की बात करें, तो इसकी कीमत में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में शुक्रवार को इसका रेट 1300 रुपए क्विंटल पहुंच गया। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमत में और बढ़ोतरी हो सकती है।

नासिक मंडी में ये है प्याज का दाम

27 जून को नासिक मंडी में प्याज का औसतन भाव 1201 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं, अगले दिन इसकी कीमत में 79 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस तरह 28 जून को प्याज की कीमत बढ़कर 1280 प्रति क्विंटल हो गई। वहीं, 29 जून को प्याज का रेट 1280 से बढ़कर 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया।

टमाटर के बाद प्याज महंगी होने से आम जमता परेशान हो गई है। लोगों का कहना है कि इसी तरह से प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ती रहीं, तो आने वाले दिनों में खाने के लाले पड़ जाएंगे।

सरकार ने इतने खरीदे स्टॉक

सरकार ने करीब दो महीने पहले किसानों से करीब 0.14 मिलियन टन प्याज का स्टॉक खरीदा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अप्रैल में कहा था कि केंद्र सरकार 2023-24 सीजन के लिए 3 लाख टन प्याज बफर स्टॉक में रखेगी। वहीं पिछले सीजन 2022-23 के लिए 2.51 लाख टन प्याज बफर स्टॉक में रखे गए थे। दूसरी ओर, भारत सरकार ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि 2021-22 में प्याज का उत्पादन 31.69 मिलियन टन से गिरकर 31.01 मिलियन टन होने का अनुमान है।

80 रुपए तक टमाटर के दाम बढ़े

देश भर में पहले उच्च गर्मी और फिर लगातार बारिश के कारण टमाटर की कीमतों पर असर पड़ा है। भारत बारिश और हद से ज्यादा गर्मी से फसल खराब होने के कारण आपूर्ति में कमी आई है। ऐसे में टमाटर की कीमतें 10 से 20 रुपए से बढ़कर 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुके हैं यानी कि प्रति किलो पर 70 से 80 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मौसम के कारण टमाटर के अलावा थोक और खुदरा बाजार में अन्य सब्जियों की कीमत बढ़ी है।

स्टील की कीमतों में बनी रह सकती है स्थिरता

नई दिल्ली ।

देश के प्रमुख इस्पात विनिर्माताओं का कहना है कि इस्पात की कीमत निचले स्तर तक जा चुकी है, भले ही इस साल की शुरुआत से इनमें गिरावट आ रही है। स्टीलमिंट के आंकड़ों पता चलता है कि इस्पात की चादरों के बेंचमार्क हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) के औसत मासिक दाम इस साल मार्च में 60,260 रुपए प्रति टन (मुंबई से बाहर) थे, जबकि 27 जून तक औसत मासिक दाम 55,443 रुपए प्रति टन थे, जिसमें पिछले महीने के मुकाबले गिरावट आई लेकिन कंपनियों का कहना है कि दामों में आगे गिरावट की संभावना नहीं है। टाटा स्टील के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा, मुझे लगता है कि दाम निचले स्तर तक जा चुके हैं। लौह अयस्क और कोयले की मौजूदा कीमत स्तर पर वैश्विक स्तर पर अधिकांश स्टील कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रमुख कच्चे माल लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के दाम पिछले कुछ दिनों में बढ़ने लगे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील और आसलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया का भी यही कहना है कि दामों में और गिरावट के आसार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पिछले कुछ सप्ताह में दामों में करीब 20 से 30 डॉलर प्रति टन तक की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए अब दाम स्थिर हो चुके हैं। गिरावट रुक गई है। लंबे उत्पादों में भी यह गिरावट द्वितीयक

क्षेत्र की क्षमता से कहीं अधिक रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से लंबे उत्पादों में सरिए में गिरावट आ रही है।

गेहूं हुआ सस्ता, दाल अभी भी महंगी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने जून में अरहर और उड़द तथा गेहूं की भंडारण सीमा तय कर दी थी, जिससे इनकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। इन अनाज की कीमत कई वजहों से बढ़ी हुई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग और कारोबारियों के आंकड़ों से पता चलता है कि भंडारण की सीमा तय किए जाने के बाद से दिल्ली के बाजार में जहां गेहूं की कीमत घटी है लेकिन अरहर और उड़द के मामले में ऐसा नहीं है। गेहूं के मामले में भी देखें तो उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कीमत में गिरावट सभी केंद्रों पर एक समान नहीं कम हुई है। कुछ केंद्रों पर भंडारण की सीमा तय किए जाने के बाद भी गेहूं की थोक कीमत बढ़ी है। व्यापारियों ने कहा कि अकोला, गुलबर्ग, लातूर, चेन्नई और विजयवाड़ा जैसी जगहों पर अरहर और उड़द कीमत कम होनी शुरू हुई है, जिसका असर इसका उपभोग करने वाले इलाकों में अगले कुछ सप्ताह में पड़ेगा। मई से जुलाई तक की अवधि को दलहन के लिए सुस्त मौसम माना जाता है। खरीफ की फसल तैयार होने के साथ गतिविधियां तेज हो जाती हैं।

इंटरनेट बंद होने से पहली छमाही में देश को 1.9 अरब डॉलर का नुकसान: रिपोर्ट

मुंबई ।

इंटरनेट बंद होने के कारण 2023 की पहली छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था को 1.9 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाल ही में पंजाब और मणिपुर में प्रशासन ने इंटरनेट-बंद किया। वैश्विक गैर-लाभकारी इकाई इंटरनेट सोसायटी ने अपनी रिपोर्ट नेटलॉस में बताया कि बंदी से लगभग 11.8 करोड़ डॉलर के विदेशी निवेश का भी नुकसान हुआ है और लगभग 21,000 नौकरियां भी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारें अक्सर यह गलत धारणा बना लेती हैं कि इंटरनेट बंद करने से अशांति कम होगी, भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर रोक लगेगी या साइबर सुरक्षा खतरों से नुकसान की आशंका कम हो जाएगी लेकिन बंदी से आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए भारत में लगातार इंटरनेट बंद किए जाने के कारण यहां इस साल अब तक इसका जोखिम 16 प्रतिशत हो गया है, जिससे भारत दुनिया में इस साल सबसे ज्यादा जोखिम वाले देशों में से एक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट बंद होने से ई-कॉमर्स बंद हो जाता है, जिससे त्वरित किए जाने वाले लेन-देन नहीं होने से घाटा होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, व्यापार-ग्राहक संवाद बाधित होता है और कंपनियों के लिए वित्तीय एवं साख संबंधी जोखिम पैदा होते हैं। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि वह बंदी के खिलाफ है और

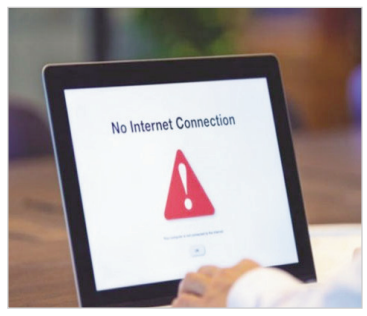

उसने सरकारों से इसे लागू करने से परहेज करने का आग्रह किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था, समाज और इंटरनेट ढांचा प्रभावित होते हैं।

सेबी ने आईपीओ की लिस्टिंग और एफपीआई को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किए

नई दिल्ली ।

शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर एक आम निवेशक पर होगा। इसमें आईपीओ की लिस्टिंग, एनसीडी (एनसीडी) की लिस्टिंग, किसी एक विशेष कॉरपोरेट हाउस में जरूरत से ज्यादा निवेश करने वाले एफपीआई के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर देना होगा। माना जा रहा था कि इस बार म्यूचुअल फंड में टीईआर को नियमों पर कोई ऐलान हो सकता है। सेबी की ओर से लिए गए फैसले के मुताबिक, अब एक विशेष कॉरपोरेट में पैसा लगाने वाले एफपीआई को नया नियम आने के बाद एक अतिरिक्त डिस्क्लोजर देना होगा। इसमें एफपीआई को अपने स्ट्रक्चर से लेकर किस मकसद से उस कंपनी में निवेश किया जा रहा है। ये बताना होगा। सेबी ने शेयर बाजार में नए आईपीओ की लिस्टिंग के समय को घटाने का फैसला किया है। अब आईपीओ बंद होने के तीन दिनों के अंदर ही लिस्टिंग हो सकती है। शुरुआत में पहले चरण में स्वैच्छिक रूप से ये नियम लागू होगा। जो कि एक सितंबर 2023 से शुरू होगा। इसका दूसरा चरण दिसंबर 2023 से लागू होगा। सभी आईपीओ इश्यू पर लागू हो जाएगा।

नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। जो एक जनवरी से लागू होने हैं। इसके बाद नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी की लिस्टिंग और स्वैच्छिक आधार पर डीलिस्टिंग की जा सकेगी। बता दें, इस बार की बैठक में म्यूचुअल फंड में टीईआर (टोटल एक्सपेंस रेश्यो) को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।

अदाणी टोटल गैस 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी

मुंबई ।

अदाणी समूह की कंपनी अदाणी टोटाल गैस (एटीजीएल) और फ्रांसीसी ऊर्जा दिग्गज टोटल एनर्जीज अगले 8-10 सालों में गैस डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 18,000-20,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। अदाणी टोटल गैस की वित्त वर्ष 23 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने कहा कि वह अधिक सीएनजी स्टेशनों को जोड़ने, अपने पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निवेश का उपयोग करेगी। बता दें कि कंपनी के पास वर्तमान में 460 सीएनजी स्टेशन और पाइप्ड कुकिंग गैस के 7 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का नेटवर्क है। कंपनी के एक व रिष्ठ अ धिकारी ने कहा कि अदाणी टोटल पूरे भारत में 3,000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के बरसाना में 600 टीपीडी की शुरुआती क्षमता के साथ भारत के सबसे बड़े बायोमास संयंत्रों में से एक को चालू कर रहे हैं। कंपनी भारत में गैस के भविष्य को लेकर आशावादी है, क्योंकि सरकार 2030 तक देश के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करना चाहती है। एटीजीएल ने वित्त वर्ष 23 में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए कम से कम 1,150 करोड़ का निवेश किया है।

सेंको गोल्ड का आईपीओ 4 जुलाई को खुलेगा

कोलकाता ।

कोलकाता स्थित सेंको गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में है। कंपनी का आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) निवेशकों के लिए आवेदन करने के लिए 4 जुलाई को खुलेगा और निवेशक 6 जुलाई तक आईपीओ में आवेदन कर सकेंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 301-317 रुपए प्रति शेयर तय किया है। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर के हिसाब से कंपनी को 2460 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन मिल रहा है। सेंको गोल्ड आईपीओ के जरिए निवेशकों से 405 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। जिसमें 270 करोड़ रुपए नए शेयर जारी कर जुटाए जाएंगे, जबकि 135 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाए जाएंगे। इसका मतलब है कि मौजूदा निवेशक आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी ने कहा कि बुक रनिंग लीड मैनेजर्स से बात करने के बाद फ्लोर प्राइस और ऑफर प्राइस तय किया जाएगा। आईपीओ का 50 प्रतिशत संस्थागत निवेशकों के लिए 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए और 35 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है। कंपनी सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स ब्रांड के नाम से आभूषणों के खुदरा क्षेत्र में मौजूद है। कंपनी सोने, हीरे, प्लैटिनम के आभूषणों के साथ-साथ चांदी के आभूषण भी बेचती है। कंपनी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी खुदरा आभूषण कंपनी है। कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी आभूषण बेचती है।

शिखर धवन की होने जा रही है वापसी, इस बड़े टूर्नामेंट में कर सकते हैं टीम इंडिया की कप्तानी

मुम्बई(एजेंसी)। लगातार कुछ समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक शिखर धवन टीम इंडिया का नेतृत्व एशियन गेम्स 2022 में कर सकते हैं। वहीं, इसके लिए एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण को कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच चीन में हो रहा है। एशियन गेम्स में बीसीसीआई ने पुरुष और महिला टीम भेजने को लेकर सहमति दे दी है। ऐसे में टीम इंडिया का नेतृत्व शिखर धवन कर सकते हैं।

बीसीसीआई भेजेगी दोयम दर्जे की टीम

माना जा रहा है कि बीसीसीआई एशियन गेम्स के लिए दोयम दर्जे की टीम भेजेगी। इस टीम का नेतृत्व शिखर धवन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप की तारीखें टकरा रही हैं। ऐसे में यह माना जा सकता है कि शिखर धवन की अब वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में वापसी नहीं होगी। लेकिन एशियन गेम्स में वह टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे। अगर वर्ल्ड कप में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है तो उन्हें एशियन गेम्स में खेलते हुए देखा जा सकता है। शिखर धवन टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं। हालांकि, 37 वर्षीय शिखर धवन ने अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

आईपीएल में कितने कप्तानी

आईपीएल 2023 में शिखर धवन ने पंजाब की कप्तानी की थी। शिखर धवन को बड़े टूर्नामेंट का खिलाड़ी माना जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में शिखर 90.75 की औसत से 363 रन बनाए थे। उनका बल्ला वर्ल्ड कप, एशिया कप और टी20 विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी चला है। शिखर धवन ने 68 टी-20 मुकाबले खेले हैं, जबकि 167 वनडे इंटरनेशनल में उन्हें खेलने का मौका मिला है। 34 टेस्ट मुकाबले में शिखर धवन ने टीम इंडिया की ओर से खेले हैं। वहीं आईपीएल में अलग-अलग टीमों से उन्होंने 217 मुकाबले खेले हैं।

वीनस विलियम्स 24वें विम्बलडन में स्वितोलिना के खिलाफ करेंगी शुरुआत

विम्बलडन (इंग्लैंड) (एजेंसी)। पांच बार की विम्बलडन चैम्पियन वीनस विलियम्स 24वीं बार यहां टेनिस ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में खेलने उतरेंगी जिसमें वह अपना अभियान एलिना स्वितोलिना के खिलाफ शुरू करेंगी जो 2019 के सेमीफाइनल में पहुंची थी।

शुक्रवार को निकाले गए विम्बलडन ड्रा में दो बार यहां खिताब जीत चुके एंडी मरे पहले दौर के मैच में वाइल्ड कार्ड से प्रवेश करने वाले रेयान पेनिस्टन से भिड़ेंगे जो ब्रिटेन के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होगा। वीनस (43 वर्ष) ने इस सत्र में केवल पांच मैच खेले हैं और अप्रैल में टूर में वापसी करने वाली स्वितोलिना दोनों को आल इग्लैंड क्लब ने वाइल्ड कार्ड दिया है।

इस मैच की विजेता खिलाड़ी दूसरे दौर में 28वीं वरीय एलिसे मर्टन्स और इसके बाद सातवें नंबर की अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफसे भिड़ सकती हैं। गॉफ ने 2019 में विम्बलडन में वीनस को हराकर अपना ग्रैंडस्लैम करियर शुरू किया था, तब वह महज 15 वर्ष की थी। वीनस 2000, 2001, 2005, 2007 और 2008 की विम्बलडन विजेता हैं और दो बार अमेरिकी ओपन ग्रैंडस्लैम जीत चुकी हैं।

मरे और पेनिस्टन के बीच मैच के विजेता की भिड़ंत पांचवें वरीय स्टेफनोस सिटसिपास या 2020 अमेरिकी ओपन चैम्पियन डोमिनिक थिएम से होगी। साल का तीसरा ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट सोमवार (तीन जुलाई) से शुरू होगा जिसमें दूसरे वरीय नोवाक जोकोविच लगातार पांचवीं और कुल आठवीं चैम्पियनशिप जीतने के लिए पदार्पण कर रहे अर्जेंटीना के पेड्रो काचिन (67वीं रैंकिंग) के खिलाफ मैच से शुरूआत करेंगे।

ओमान पर जीत के बाद विश्व कप क्वालीफिकेशन के एक कदम करीब पहुंचा जिम्बाब्वे

बुलावायो (एजेंसी)। सीन विलियम्स के लगातार दूसरे शतक से जिम्बाब्वे ने गुरुवार को यहां आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर के सुपर सिक्स चरण में ओमान पर 14 रन की जीत दर्ज की जिससे वह भारत में होने वाले 50 ओवर के महासमर के एक कदम करीब पहुंच गया।

जिम्बाब्वे ने यहां अपने पहले मैच में ग्रुप ए के प्रदर्शन को जारी रखते हुए ओमान को पराजित किया जिसमें विलियम्स की शानदार फॉर्म जारी रही। ग्रुप चरण में चारों मैच जीतने वाली मेजबान टीम जिम्बाब्वे के अब सुपर सिक्स चरण में छह अंक हो गये हैं जबकि चार अंक उसे ग्रुप चरण से मिले थे।

ओमान ने कश्यप प्रजापति (103 रन) के शतक से 333 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी जोर लगाया लेकिन टीम 50 ओवर में नौ विकेट पर 318 रन ही बना सकी। जिम्बाब्वे ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद विलियम्स के 142 रन (103 गेंद) से सात विकेट पर 332 रन बनाए। विलियम्स अभी तक टूर्नामेंट की पांच पारियों में तीन शतक जड़ चुके हैं और एक 91 रन की पारी खेल चुके हैं।

खिलाड़ियों के विदेशी लीग में भाग को रोकने नियम ला सकता है बीसीसीआई

-खिलाड़ियों के विदेशी टी20 लीग का रुख करने से बोर्ड चिन्तित

मुम्बई(एजेंसी)। क्रिकेटर सुरेशा रैना के बाद जिस प्रकार बल्लेबाज अंबाति रायुडू ने विदेशी टी20 लीग की ओर अपना रुख किया है। उससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) चिन्तित हो गया है। इसका कारण से है कि खिलाड़ी अब तीस से कम उम्र में ही संन्यास लेकर विदेशी लीग जाने लगे हैं। इसी को देखते हुए बीसीसीआई अब सात जुलाई को होने वाली अपनी शीर्ष परिषद की बैठक में विदेशी टी20 लीग में खिलाड़ियों के भाग लेने की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगा। पिछले तीन साल से कई स्टार क्रिकेटर घरेलू क्रिकेटर से संन्यास लेकर विदेशी टी20 लीग खेल रहे हैं। इसमें रैना के अलावा , युवराज सिंह, हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। वहीं अब इनमें रायुडू का नाम भी जुड़ गया है। घरेलू क्रिकेटर भी 30 की उम्र होने से पहले ही क्रिकेटर संन्यास ले रहे हैं और विदेशी टी20 लीग में भाग ले रहे है। इन हालातों को देखते हुए बीसीसीआई अब कड़े नियम ला रहा है।

बीसीसीआई पंजीकृत खिलाड़ियों को तभी विदेशी टी20 लीग में हिस्सा लेने की अनुमति देता है जब वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) भी शामिल है। रायुडू ने पिछले महीने चेन्नई सुपरकिंग्स की खिताबी जीत में भूमिका निभाने के बाद आईपीएल से संन्यास ले लिया था। अब वह जुलाई में अमेरिका में होने वाली शुरुआती मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) में टेक्सास सुपरकिंग्स में खेलते हुए नजर आएंगे। बीसीसीआई अपने सक्रिय खिलाड़ियों को टी20 लीग में हिस्सा लेने से बचाना चाहता है और ताजा घटनाक्रम को देखते हुए वह अपने रिटायर्ड खिलाड़ियों की भागीदारी पर एक अनुच्छेद ला सकता है। घरेलू क्रिकेट का स्तर और ज्यादा कमजोर नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वह ऐसा कर सकता है क्योंकि टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट के फैलने से काफी खिलाड़ी जल्दी संन्यास ले सकते हैं।।

सबसे अधिक टेस्ट शतक के मामले में वॉ की बराबरी पर पहुंचे स्मिथ

-विराट , रुट और विलियमसन को पीछे छोड़ा

लंदन । अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की शतकीय पारी 110 रनों की सहायता से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहां लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 416 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्मिथ ने 110 रन बनाये। इस प्रकार स्मिथ ने 32 वां टेस्ट शतक लगाया है। स्मिथ ने पहले दिन के 85 रन से आगे खेलते हुए जेम्स एंडरसन की गेंद पर चौका लगाकर शतक बनाया। स्मिथ ने इससे पहले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में भारतीय टीम के खिलाफ शतक लगाया था। यह उनका इंग्लैंड के खिलाफ 12वां टेस्ट शतक था। इस प्रकार वह सबसे अधिक टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पूर्व कप्तान स्टीव वॉ के बराबर आठवें स्थान पर पहुंच गये हैं।

विनेश और बजरंग प्रशिक्षण के लिए किर्गिस्तान और हंगरी जाएंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलवान बजरंग पूनिया और महिला पहलवान विनेश फोगाट जुलाई के पहले सप्ताह में ही प्रशिक्षण शिविरों के लिए किर्गिस्तान और हंगरी जाएंगे। ये दोनो ही ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) योजना के तहत भेजे जा रहे हैं। खेल मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों ने युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) की टॉप्स टीम को अपने प्रस्ताव भेजे थे। जिन्हें स्वीकार कर दिया गया है। बजरंग 36 दिनों के प्रशिक्षण शिविर के लिए इस्सिक-कुल, किर्गिस्तान जाएंगे जबकि विनेश पहले एक सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए बिश्केक, किर्गिस्तान जाएंगी और फिर 18 दिनों के प्रशिक्षण शिविर के लिए हंगरी जाएंगी।

विनेश के साथ इस दौरे में फिजियोथेरेपिस्ट अश्विनी जीवन पाटिल, स्पैरिंग पाटर्नर संगीता फोगाट और कोच सुदेश भी रहेंगे। वहीं बजरंग के साथ कोच सुजीत मान, फिजियोथेरेपिस्ट अनुज गुप्ता, स्पैरिंग पाटर्नर जितेंद्र और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग विशेषज्ञ काजी हसन रहेंगे। सरकार विनेश, बजरंग के अलावा संगीता फोगाट और जितेंद्र को भी प्रशिक्षण के लिए भेजेगी।

अब राजनीति में उतरेंगे रायुडू

हैदराबाद । क्रिकेटर अंबाती रायुडू अब राजनीति में प्रवेश करेंगे। आंध्र प्रदेश से निकलकर टीम इंडिया की ओर से खेलने वाले रायुडू ने विश्वकप में जगह नहीं मिलने के बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए खेल से संन्यास ले लिया था। वहीं आईपीएल में उन्होंने इसी साल चेन्नई सुपर किंग्स की खिताबी जीत के बाद आईपीएल से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद अब रायुडू राजनीति में उतरने जा रहे हैं। वह मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की सदस्यता लेंगे। 37 वर्षीय इस क्रिकेटर ने अपना आखिरी क्रिकेट मैच 29 मई को आईपीएल विनर एमएस धोनी की कप्तानी वाली विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फाइनल में खेला था। रायुडू ने घरेलू क्रिकेट में हैदराबाद की ओर से खेला था। यह अब राज्य के विभाजन के बाद तेलंगाना का हिस्सा हो गया है। वह जमीनी स्तर पर लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को समझने के लिए पिछले कुछ दिनों से गुंटूर जिले का दौरा कर रहे हैं। रायुडू ने कहा, मैं लोगों की सेवा करने के लिए जल्द ही आंध्र प्रदेश की राजनीति में प्रवेश करूंगा। इससे पहले मैंने लोगों की समस्याओं को समझने के लिए जिले के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने का फैसला किया है। इस क्रिकेटर ने उन अटकलों का खंडन किया कि वह गुंटूर या मछलीपट्टनम संसदीय क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि रायुडू ने हाल ही में अमीनाबाद गांव में मुलंकारेश्वरी मंदिर का दौरा किया और पूजा की। उन्होंने फिरंगीपुरम में साई बाबा मंदिर और बाला येसु चर्च में भी प्रार्थना की।

रहाणे को टेस्ट उप कप्तान बनाये जाने से हैरान हैं गांगुली

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि वेस्टइंडीज दौरे के लिए बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया जाना हैरानी भरा फैसला है। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली के अनुसार रहाणे की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है, ऐसे में उनकी जगह किसी अन्य को ये जिम्मेदारी देनी चाहिये थी। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में निरंतरता और स्थिरता लाने की जरुरत है। खराब फार्म के कारा रहाणे करीब डेढ़ साल तक भारतीय टीम से बाहर रहे थे। आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें विश्वटेस्ट चैम्पयनशिप फाइनल के लिए शामिल किया गया था। रहाणे ने फाइनल में वह 89 और 46 रन की पारियां खेलीं थी।

गांगुली के अनुसार केवल एक टेस्ट के आधार पर ही चयन समिति ने रहाणे को फिर से उप कप्तान नियुक्त कर दिया जबकि किसी युवा को ये जिम्मेदारी देकर भविष्य के लिए तैयार किया जाना बेहतर विकल्प रहता। उन्होंने हालांकि रहाणे को उप-कप्तान बनाने के फैसले को व्यावहारिक फैसला भी नहीं बताया। उन्होंने कहा, 'मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यह पीछे की ओर उठाया गया कदम है। आप 18 महीने से बाहर हो, फिर आप एक टेस्ट खेलते हो और आपको उप कप्तान बना दिया जाता है। मुझे इसके पीछे का आधार समझ नहीं आया। उपकप्तानी के लिए ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा भी बेहतर विकल्प थे।

वहीं चयनकर्ताओं ने चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज को बाहर करके बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और गांगुली चाहते हैं कि एक खिलाड़ी के साथ के साथ संवाद स्पष्ट होना चाहिए जो भारत के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुका हो। उन्होंने कहा, 'चयनकर्ताओं को पुजारा के बारे में स्पष्ट होना चाहिए था। क्या वे उसे टेस्ट क्रिकेट में और खिलाना चाहते हैं या फिर वे युवाओं के साथ जारी करना चाहते हैं, उसे इस बारे में बताया जाना चाहिए था। साथ ही कहा कि पुजारा जैसे कद के खिलाड़ी को आप टीम से बाहर, फिर अंदर और फिर बाहर, फिर अंदर नहीं कर सकते।

पोलैंड में जासूसी के आरोप में रुसी खिलाड़ी पकड़ाया

वारसॉ । पोलैंड ने आज जासूसी के आरोप में एक रुसी हॉकी खिलाड़ी को पकड़ा है। अधिकारियों के अनुसार खिलाड़ी यह रुसी खिलाड़ी पोलैंड की शीर्ष हॉकी लीग में खेलता है। पोलैंड के न्याय मंत्री बिगन्यू जियोब्रो ने कहा, 'रूस के जासूस एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'एक खिलाड़ी के रुप में काम कर रहे एक जासूस को पकड़ा गया है। जियोब्रो ने कहा कि यह संदिग्ध एथलीट पहले लीग क्लब के लिए खेलता था। साथ ही कहा कि अब तक ऐसे 14 लोग जासूसी के आरोप में पकड़े गये हैं।

पूर्व क्रिकेटर बोला, जडेजा और अक्षर निभाएंगे विश्वकप में युवराज की भूमिका

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज के श्रीकांत का मानना है कि इस बार विश्वकप में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल अहम भूमिका निभाएंगे। श्रीकांत के अनुसार जिस प्रकार 2011 विश्वकप में ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भारतीय टीम की जीत में विशेष योगदान दिया था वैसा ही कुछ ये दोनो भी करेंगे। भारती टीम पिछले एक दशक से आईसीसी खिताब नहीं जीत पायी है और ऐसे में उसका लक्ष्य इस बार खिताब जीतना रहेगा।

श्रीकांत ने कहा, साल 2011 विश्व कप में, हमन बहुत सारे ऑलराउंडरों को खेलते हुए देखा। हमारे पास एक शानदार टीम थी, जिसका नेतृत्व महेन्द्र सिंह धोनी कर रहे थे। उस समय हमारे पाय युवराज जैसा आक्रामक ऑलराउंडर था। अब मेरा मानना है कि जड़ेजा और अक्षर भी वही करेंगे जो युवराज सिंह ने 2011 विश्व कप में किया था। मेरा मानना है कि अगर भारत को 2023 विश्व कप जीतना है तो ये लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जडेजा कई वर्षों से तीनों प्रारूपों में भारत के लिए सबसे मूल्यवान खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। जडेजा ने 174 एकदिवसीय मैच खेले हैं और 32.80 की औसत से 2526 रन बनाए हैं, जिसमें 13 अर्द्धशतक शामिल हैं। उन्होंने इस प्रारूप में 37.39 की औसत से 191 विकेट भी लिए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने में मदद की। ऐसे में इस ऑलराउंडर से आगामी विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी। वहीं दूसरी ओर, अक्षर पटेल भारत की 2015 विश्व कप टीम का हिस्सा थे हालांकि वह तब एक भी मैच नहीं खेल पाये थ। इस खिलाड़ी ने आईपीएल के 16 वें सत्र में जिस प्रकार दबाव के बीच भी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि वह इस बार विश्वकप में अंतर पैदा कर सकते हैं।

शीर्ष पाकिस्तानी खिलाड़ी माजिद अली ने की आत्महत्या, इस बीमारी से थे पीड़ित

करांची। प्रसिद्ध पाकिस्तानी स्नूकर खिलाड़ी और एशियाई अंडर-21 रजत पदक विजेता माजिद अली ने गुरुवार को पंजाब में फैसलाबाद के पास अपने गृहनगर समुंदरी में आत्महत्या कर ली। वह 28 वर्ष के थे। पुलिस के अनुसार माजिद अपने खेल के दिनों से ही कथित तौर पर अवसाद से पीड़ित थे और उसने लकड़ी काटने वाली मशीन का उपयोग करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय सर्किट में शीर्ष क्रम के खिलाड़ी थे। माजिद एक महीने में मरने वाले दूसरे स्नूकर खिलाड़ी हैं। पिछले महीने एक अन्य अंतरराष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी मुहम्मद बिलाल की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। उनके भाई उमर ने कहा कि माजिद किशोरावस्था से ही अवसाद से पीड़ित था और हाल ही में उसे एक और अवसाद का सामना करना पड़ा। उमर ने कहा, 'यह हमारे लिए भयावह बात है क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी जान ले लेगा। पाकिस्तान बिलियड्र्स और स्नूकर के अध्यक्ष आलमगीर शेख ने कहा कि माजिद की मौत से पूरा समुदाय दुखी है। उन्होंने कहा, 'उनमें बहुत प्रतिभा थी और वह युवा थे और हमें उनसे पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बहुत उम्मीद थी।' शेख ने कहा कि माजिद को कोई वित्तीय समस्या नहीं थी। मुहम्मद यूसुफ और मुहम्मद आसिफ जैसे सितारों द्वारा विश्व और एशियाई चैम्पियनशिप खिताब जीतने में मदद करने के बाद स्नूकर देश में एक हाई-प्रोफाइल खेल बन गया है जबकि कुछ खिलाड़ी पेशेवर सर्किट में भी स्नातक हो गए हैं।

एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास,

इरान को मात देकर 8वीं बार बना चैंपियन, अनुराग ठाकुर ने दी शुभकामनाएं

मुम्बई (एजेंसी)। भारत ने शुक्रवार को डोंग यूई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सियोकडांग सांस्कृतिक केंद्र में खेले गए फाइनल मुकाबले में ईरान को मात दे दी है। ईरान को हराकर भारत ने ऐतिहासिक रूप से 8वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में ईरान को 42-32 से मात देकर इस खिताब को हासिल किया है।

अब तक नौ बार खेली गई ये चैंपियनशिप भारत के ही कब्जे में रही है। इस टूर्नामेंट में भारत ने आठ बार रिकॉर्ड जीत हासिल की है जबकि ईरान ने वर्ष 2003 में एक बार जीत दर्ज की थी। खेल में शुरुआत में भारतीय टीम पिछड़ती रही, मगर बाद में टीम ने शानदार वापसी की। भारतीय टीम ने 10वें मिनट में कप्तान पवन सहरावत और असलम इनामदार की सफल रेड की बदौलत ईरान की पूरी टीम को ही ऑल ऑउट कर दिया। इस मुकाबले में कप्तान ने पवन ने सुपर 10 भी हासिल किया।

भारतीय टीम ने मुकाबले में अपनी दमदार लय बरकरार रखी। ईरान के खिलाफ इस दमदार प्रदर्शन के दम पर ही भारतीय टीम अच्छी लीड लेने में सफल रही। हालांकि मुकाबले में भारत की भूल के कारण ईरान को कुछ बढ़त मिली मगर भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी तेज रफ्तार से ईरान को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और टीम को ऑल आउट कर दिया।

जानकारी के मुताबिक मुकाबले के पहले हाफ में भारत के पास 23-11 से बढ़त थी, जिसके बाद ईरान के कप्तान मोहम्मदरेज़ा शादलू चियानेह ने दो अंकों की रेड कर सुपर रेड की और भारत को पहली बार 29वें मिनट में आउट किया। दो मिनट बचे रहने के दौरान ईरान की टीम ने बढ़त बनाने की कोशिश की मगर भारतीय टीम ने ईरान को इसका मौका नहीं दिया और अंत में मुकाबला 42-32 के साथ अपने नाम किया। इसी के साथ चैंपियनशिप पर भी भारत का कब्जा हुआ।

अनुराग ठाकुर ने दी शुभकामनाएं

भारतीय टीम द्वारा इतिहास रचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीटर पर टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, 8वीं बार चैंपियन। भारतीय टीम ने मैट पर अपने पूर्ण प्रभुत्व और अजेय रिकॉर्ड के साथ 2023 एशियाई सकबड्डी चैंपियनशिप में झंडा बुलंद रखा है। मजबूत प्रतिद्वंद्वियों ईरान के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ अपने खिताब का बचाव करना उनके विश्वास, कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट टीम प्रयास का प्रतिबिंब है। शाबाश, चैम्प्स। बहुत उत्साहित हूं और एशियाई खेलों में उन्हें एक्शन में देखने के लिए उत्सुक हूं।

फीफा रैंकिंग में 100 वें स्थान पर पहुंची भारतीय फुटबॉल टीम

नई दिल्ली । भारतीय फुटबॉल टीम विश्व फुटबॉल की शीर्ष संस्था (फीफा) की ताजा रैंकिंग में एक स्थान के लाभ के साथ ही 100 वें स्थान पर पहुंच गयी है। पांच साल में यह पहली बार है कि भारतीय टीम शीर्ष 100 में पहुंची है। भारतीय टीम साल 2018 में 97वें स्थान पर थी। इससे पहले अप्रैल में भारतीय टीम फीफा रैंकिंग में 101वें स्थान पर पहुंची थी। जून में इंटरकांटिनेंटल कप और सैफ चैंपियनशिप में एक भी मैच नहीं हारने के कारण उन्हें 4.24 अंक मिले थे। जिससे उन्हें शीर्ष 100 में पहुंचने में सहायता मिली है। भारतीय टीम साल 2022 वीएफएफ ट्राई-नेशन सीरीज़ में वियतनाम के हाथों 0-3 की हार के बाद से ही एक भी मैच नहीं हारी है। उन्होंने साल 2023 में नौ में से सात गेम जीते हैं जबकि दो बार मुकाबले बराबरी पर रहे हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने इस साल दो खिताब भी जीते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

परिचय

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य के मूल्यों में अत्यधिक उतार - चढ़ाव, मौसमी और कम समय के लिए मूल्य वृद्धि और अनियमित मानसून को देखते हुए कृषि क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों के लिए एह एक कठिन चुनौती है। इसके बावजूद किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को अवश्य हासिल किया जा सकता है। खेत उत्पादकता में सुधार लाने, खेती की लागत को कम करने, अखिल भारतीय स्तर पर बाजार पहुँच को सुनिश्चित करने आदि की दिशा में सामूहिक प्रयास से इस लक्ष्य की प्राप्ति में काफी आसानी हो सकती है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। की इस लक्ष्य को हासिल करने में कंदीय फसलों की मुख्य भूमिका होगी।

कंदीय फसलों से भरपूर आमदनी

बागवानी से भरपूर आय

बागवानी क्षेत्रों में किसानों की आय को बढ़ाने की भरपूर क्षमता है। इसलिए पारंपरिक अनाजीय फसलों से उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की ओर बदलाव करने से से भारत में किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में व्यापक पैमाने पर योगदान किया जा सकेगा। बागवानी फसलों में भी विशेषत=कंदीय फसलें इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें अभूतपूर्व उच्च प्रति इकाई उत्पादकता पाई जाती है। हालाँकि एक सम्यक रीति में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्पादन क्लस्टरों को इनपुट के साथ - साथ उपभोक्ता बाजारों से अच्छी तरह से जोड़ने की जरूरत है यह संदेह से परे है कि कृषि इनपुट और उत्पादन से जुड़े सूक्ष्म - लघु - छोटे तथा माध्यम स्तरीय उद्यमों की स्थापना से ग्रामीण भारत की आजीविका सुरक्षा में प्रभावी तरीके से सुधार किया जा सकता है। कंदीय फसलें ग्राम स्तर पर ही ऐसे उद्यमों को स्थापित करने के भरपूर अवसर प्रदान करती हैं। कंदीय फसल अनुसंधान पर कहीं अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें शामिल है= गैर- पारंपरिक क्षेत्रों में इनकी खेती का विस्तार करना, कंदीय फसलों की पोषणिक एवं खाद्य सुरक्षा भूमिका का पूर्वानुमान करना, मूल्यवर्धित खाद्य, आहार एवं औद्योगिक उत्पादों का विकास करके उपयोगिता संभावनाओं को बढ़ाना, अमंग आकलन रण नीतियाँ विकसित करना, नये बाजार विकल्पों की तलाश करना, औषधीय प्रभावों वाले हर्बल उत्पादों, जैव कीटनाशकों, प्राकृतिक खाद्य रंगों का विकास करना जैसे अल्प दोहित क्षेत्रों की खोज करना आदि। प्रौद्योगिकीय प्रगति का प्रभावी तरीके सेड प्रदर्शन और प्रसार करने. उत्पादकता में और सुधार करने और ग्रामीण जनसंख्या तक लाभ पहुँचाने के लिए इन फसलों की उपयोगिता संभावनाओं का खुलासा करने में काफी मदद मिल सकती है।

कंदीय फसलों में मूल्यवर्धन

उष्णकटिबंधीय कंदीय फसलों में न केवल खाद्य फसलों के रूप में महत्ता हासिल की है वरन इनकी आहार और कृषि आधारित उद्योगों में भी व्यापक संभावनाएं हैं। खाने - पीने की आदतों में तेजी से हो रह बदलाव और प्रति व्यक्ति आमदनी में अनुमानित बढ़ोतरी के साथ शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते देशांतर से अगले 30 - 40 वर्षों में प्रसंस्करित और रेडी टू ईट (खाने के लिए तुरंत तैयार) सुविधाजनक खाद्य में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। उस परिदृश्य में कंदीय फसलों से रोग - निरोधी और चिकित्सीय कार्यशील खाद्य विकसित करने की व्यापक संभावना विद्यमान है।

आलू, कसावा, शकरकंद, जिमीकंद, कचालू, टेनिया, याम (रतालू), याम बीन, अरारोट आदि जैसी कंदीय फसलें स्टार्चयुक्त भंडारण अवयव के रूप में संशोधित जड़ अथवा तने के साथ पौधों का एक समूह बनाती हैं। इनमें कहीं अधिक जड़ें, घनकंद, राइजोम्स होते है और इनके कंदों की खुदाई आमतौर पर जमीन से नीचे की जाती है। ये फसलें अनाज एवं दाना फसली के उपरांत तीसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं और प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उच्च शुष्क सामग्री उत्पादन के साथ खाद्य उत्पादक रूप में अपनी जैविक प्रभावशीलता के आधार पर ये फसलें अनूठी हैं। ऊर्जा उत्पादन में आलू सबसे आगे (216 मेगाजूल/हे./दिन) एवं इसके बाद क्रमशः रतालू (181 मेगाजूल/हे./दिन), शकरकंद (152 मेगाजूल/हे./दिन), तथा कसावा (121 मेगाजूल/हे./दिन) का स्थान है। कंदीय फसलें विश्व की 1/5 आबादी के लिए मुख्य अथवा सहायक खाद्य के तौर पर उष्णकटिबंधीय तथा अर्द्ध उष्णकटिबंधीय देशों में लाखों लोगों की

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

उपयोगी प्रौद्योगिकियां

ऐसे किसान जो आलू और अन्य कंदीय फसलों की खेती करते हैं, वे उपयुक्त फसल किस्म, आधुनिक उत्पादन एवं संरक्षण तकनीकें अथवा बचाव प्रौद्योगिकियों को अपनाकर अपनी फार्म आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। भाकृअनुप - केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम जैसे शोध संस्थानों द्वारा आलू और अन्य कंदीय फसलों की अधिक पैदवार देने वाली अनेक किस्में और प्रौद्योगिकियां विकसित की गई है। कुछ प्रौद्योगिकियां राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भी विकसित की गई हैं और वे किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इन प्रौद्योगिकियों की पहुँच अभी बहुत सीमित हैं। इन्हें किसान समुदाय के बीच लोकप्रिय बनाये जाने की जरूरत है ताकि कंदीय फसलों में वर्तमान पैदावार अंतराल को कम किया जा सके। आलू और अन्य कंदीय फसलों की उत्पदकता को बढ़ाने के लिए यहाँ प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों पर जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री

अधिकांश कंदीय फसलों को तने के टूकड़ों अथवा कंद का उपयोग करके शाकीय रूप से प्रवर्धित किया जाता है। इसलिए बीज की गुणवत्ता को बनाये रखना विशेषकर इसे वायरस तथा अन्य रोगजनकों से मुक्त रखना बहुत आवश्यक होता है। भारत में आलू उत्पादकों के समक्ष गुणवत्ता आलू बीज की उपलब्धता अभी भी एक प्रमुख समस्या है। इसीलिए यह जरूरी है कि किसानों को सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति की जाये। किसान स्वयं भी भाकृअनुप - केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा विकसित की गई बीज प्लाट तकनीक का उपयोग आलू बीज उगा सकते हैं। यह प्रौद्योगिकी पिछले 50 वर्षों से भारत में आलू के उत्पादन और उत्पादकता क्षेत्र में उल्लेखनीय बढ़ोतरी में मुख्य भोमिका निभा रही है। वायरस की पहचान करने वाली उन्नत तकनीकों, पौध बचाव उपायों और सस्यविज्ञान रीतियों के साथ बीज प्लाट तकनीक का एकीकरण करने से भारत में प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम की मजबूत बुनियाद रखने को बढ़ावा मिला है। हाल ही में हाइटेक बीज उत्पादन प्रौद्योगिकियां जैसे कि ऊतक संवर्धन से तैयार लघु कंद के साथ - साथ ऐरोपॉनिक प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार लघु कंद का विकास किया गया हैइ इन्हें गुणवत्तायुक्त आलू बीज के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐरोपॉनिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, आलू पौधों को एक बंद अथवा संरक्षित वातावरण में उगाया जाता है और मृदा अथवा किसी अन्य समुच्य मीडियम का उपयोग किये बिना पोषण से भरपूर घोल का साथ समय - समय पर जड़ों पर छिड़काव किया जाता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का तेजी से गुणन होता है, जिसमें प्रति ऊतक संवर्धन पादप 35 - 60 लघुकंद उत्पन्न होते हैं। इसमें अनेक मृदा जनित रोगजनकों के आलू कंदों के साथ सम्पर्क में कमी आती है। इसके अलावा इसे ऑपरेट करना भी आसान होता है। इस प्रणाली को गौरवायविय तथा पानी की कमी वाले इलाकों में स्थापित किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी अत्यधिक लागत प्रभावी है, जिसमें 10 लाख कंदों के उत्पादन के लिए 100 लाख रूपये का निवेश करने की जरूरत होती है और कोई भी उद्यमी इससे प्रति वर्ष 52 लाख रूपये तक कमा सकता है। अत= ऊतक संवर्धन और ऐरोपॉनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में पारंपरिक बीज उत्पादन प्रणाली में क्रन्तिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। भाकृअनुप - केंद्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम द्वारा मानकीकृत मिनी सेट प्रौद्योगिकी को अपना कर उष्णकटिबंधीय कंदीय फसलों में भी वायरसमुक्त गुणवत्ता रोपण सामग्री को विकसित किया जा सकता है।

अनाज फसलों की तुलना में कंदीय फसलों से अधिक लाभ

चावल, गेंहू और मक्का जैसे पारंपरिक अनाज फसलों की तुलना में फल व सब्जियों जैसे बागवानी फसलें कहीं अधिक लाभ प्रदान करती हैं। उच्च मूल्य वाली फसलों और उद्यमों की दिशा में कृषि गतिविधियों का विविधीकरण करना किसानों की आय को बढ़ाने में एक प्रमुख चालक बन सकता है। भारत के तीन मुख्य राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए चावल व गेहूं जैसे अनाज फसलों और प्रमुख कंदीय फसल आलू में खेत की लागत और शुद्ध आय के तुलनात्मक अध्ययन को सरणी - 1 में दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि सभी चयनित राज्यों के लिए आलू की खेती की लागत चावल और गेहूं से कहीं ज्यादा है, जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रूपये 1,08,860,30 प्रति हे. है। उत्तर प्रदेश में आलू से मिलने वाली प्रति हे. शुद्ध आय चावल और के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में आलू से मिलने वाली प्रति हे. शुद्ध आय रूपये 36,519,70 है, जो कि चावल तथा गेहूं की तुलना में लगभग तीन गुना है। बिहार में गेहूं (प्रति हे. रूपये 26,835,70) के मुकाबले आलू (प्रति हे. रूपये 32,787,00) में कहीं अधिक लाभ मिला। बिहार में किसानों के लिए धान की खेती आलू की ही तरह लाभप्रद नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें प्रति हे. केवल रूपये 6,277,70 का कम लाभ ही मिल रहा है। अत=यह देखा जा सकता है कि पारंपरिक अनाज फसलों के मुकाबले आलू जैसी कंदीय फसल की खेती करके किसान कहीं अधिक लाभ कमा सकते हैं।

उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियां

भारत में कृषि केवल लाभ अर्जित करने वाला व्यवसाय नहीं है बल्कि यह 138 मिलियन से भी अधिक कृषिजोत पर काम करने वाले परिवारों के लिए परंपरा का हिस्सा है इनमें से 85 प्रतिशत परिवारों के पास 2 हे. से भी कम आकार वाली कृषिजोत हैं। इनमें से अधिकांश कृषिजोत का उपयोग बहु कृषि गतिविधियों यथा कृषि/बागवानी, पोल्ट्री एवं पशु पालन, मत्स्यिकी, मधुमक्खी पालन रेशमा पालन तथा वानिकी में किया जाता है। इन छोटी तथा सीमांत कृषिजोत में फसलचक्र सघनता बहुत अधिक होती है। यहाँ तक कि प्राय=यह 300 प्रतिशत तक भी पहुँच जाती है।

फायदे का सौदा आलू

भारतीय समाज में आलू सर्वाधिक प्रचलित सब्जी है। देश में सब्जियों के तहत कूल कृषि में यह 21 प्रतिशत क्षेत्र में बोई जाती है और कुल सब्जी उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 25.50 प्रतिशत है। चीन के बाद भारत आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब राज्यों को शामिल करते हुए भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में देश के कुल आलू उत्पादन का 85 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन होता है। वर्ष 2014 - 15 में भारत में 23.1 टन/हे. की औसत उत्पादन हुआ। लगातर बढ़ रही जनसंख्या के साथ भविष्य में भारत में आलू की खपत कई गुना बढ़ने का अनुमान है।

जल बचत

आलू सहित किसी भी फसल की खेती के लिए सिंचाई जल इ=की म=कमी प्रमुख समस्या है। आधुनिक आलू किस्में जल की कमी वाली मृदाओं के प्रति संवेदनशील होती है और उनमें बार - बार उथली सिंचाई करने की जरूरत होती है। आमतौर पर पानी की कमी फसल की बढ़वार अवधि के मध्य से पिछेती भाग में भूस्तारी अथव स्टोलन गठन और कंद की शुरूआत तथा बल्किंग के दौरान होती है। इससे पैदावार में कमी होने की आशंका रहती है। अगेती फसलें शाकीय वृद्धि के दौरान कम संवेदनशील होती हैं। फसल पकने वाले अवधि की ओर उच्चतर रिक्तिकरण को अपनाकर भी जल की बचत की जा सकती है ताकि फसल द्वारा अपने जड़ क्षेत्र में भंडारित उपलब्ध पूरे जल का उपयोग किया जा सके। इस क्रियाविधि अथवा रीति से परिपक्वता को भी जल्दी किया जा सकता है और शुष्क पदार्थ सामग्री को बढ़ाया जा सकता है। कुछ किस्में कंद बल्किंग के अगेती भाग में सिंचाई के प्रति कहीं बेहतर प्रतिक्रिया देती हैं, जबकि अन्य बाद वाले हिस्से में कहीं बेहतर प्रतिक्रिया को दर्शाती हैं। कम कंदों वाली किस्में आमतौर पर अनके कंदों वाली किस्में आमतौर पर अनेक कंदों वाली किस्मों की तुलना में जल की कमी के प्रति कम संवेदनशील होती हैं। सिंचाई के लिए सही समय का चयन करके और पौधा वृद्धि चक्र की विशिष्ट अवस्था में जल प्रयोग की उपयुक्त गहराई का प्रयोग करके आलू की फसल में जल की जरूरत को किफायती बनाया जा सकता है। अब जलमग्न अथवा बाढ़ जैसे सिंचाई की तुलना में ड्रिप एवं स्प्रिकलर विधियों के माध्यम से सटीक रूप से सिंचाई करने के लिए प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं, जो न केवल पानी की बचत करती हैं वरन साथ ही उत्पादकता को भी बढाती हैं।

उन्नत फसलोत्तर प्रबंधन

खुदाई अथवा तुड़ाई करने के उपरांत, छिल्कों के उपचार हेतु कंदों को 10 - 15 दिनों तक ढेर में रखा जाना चाहिए। यह जरूरी है की सभी क्षतिग्रस्त और सड़े हुए कंदों को हटा दिया अच्छा लाभ कमाने के लिए उत्पाद अर्थात कंदों की छटाई की जाये और उन्हें ग्रेडिंग के अनुसार जूट के थैलों में पैक किया जाए। किसान अधिक लाभ कम सकते है यदि अपने आलू को शीत भंडार में भंडारित किया जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए भंडारित किये गये आलू स्वाद में मीठे नहीं होंगे और इस प्रकार इनसे कहीं अधिक मूला हासिल किये जा सकता है। यह ध्यान दिया जाये कि बीज आलू को केवल 0 - 20 सेल्सियस तापमान पर ही भंडारित किया जाये। चिप्स, फ्रेंच फ्रेंचाइज, लच्छा आदि जैसे निर्जलीकृत आलू उत्पादों को तैयार करके आलू में मूल्यवर्धन करने से भी किसानों को आकर्षक लाभ मिल सकता है। भाकृअनुप - केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में घरेलू स्तर पर मूल्य वर्धन करने की प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं।

ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु की उम्र 14 वर्ष और नीदरलैंड में उम्र का बंधन हटाने की तैयारी

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में ब्रेन डेड लोगों को इच्छा मृत्यु दिए जाने की न्यूनतम उम्र 14 साल करने का कानून प्रस्तावित किया जा रहा है। अभी ऐसे मामलों में 18 साल की उम्र का बंधन है।अगर यह कानून पास हो जाता है,तो इच्छा मृत्यु को लेकर दुनिया भर में यह सबसे उदार कानून होगा। जिन बच्चों का ब्रेन डेड हो गया है। उन्हें भी इच्छा मृत्यु के तहत जीवन से मुक्ति मिल सकेगी।

सैकड़ों लोगों को मिल चुकी इच्छा मृत्यु

ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2017 में कानून लागू होने के बाद,सैकड़ों लोगों को देश में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। विक्टोरिया में ऐसे लोगों की संख्या 600 के करीब है। जिन मरीजों का मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। वह बिस्तर में लेटे हुए हैं। लेकिन उम्र के बंधन के कारण उन्हें इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती है।

इच्छा मृत्यु मे उम्र का बंधन नहीं

नीदरलैंड में इच्छा मृत्यु की न्यूनतम उम्र की सीमा को खत्म किए जाने पर विचार किया जा रहा है। अभी यहां पर न्यूनतम उम्र 12 साल की निर्धारित है। नीदरलैंड में जल्द ही बच्चों को भी इच्छा मृत्यु की अनुमति देकर उन्हें लाइलाज बीमारी में असहनीय कष्ट से बचाने के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। यहां के समाज सेवियों का कहना है, बच्चों को फैसले लेने की समझ नहीं होती है। उसे इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाना कहां तक न्यायोचित होगा।

मेक्सिको में हीट वेव से 100 से अधिक मौतें – लोग घरों में कैद होने को मजबूर

मेक्सिको सिटी । मेक्सिको में भीषण गर्मी से इस साल अभी तक कम से कम 112 लोगों की मौत हो चुकी है, जो 2022 की तुलना में तीन गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो सप्ताह में गर्मी से मौत के मामले काफी बढ़ गए हैं। इस साल अभी तक गर्मी से हुई मौत के मामले 2022 की तुलना में करीब तीन गुना अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय आम तौर पर हर सप्ताह गर्मी से मौत के मामलों पर एक रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन इस बार रिपोर्ट देर से जारी की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय से गर्मी के कारण हुई मौत के मामलों की जानकारी देने में विलंब पर किए सवालों का तत्काल कोई जवाब नहीं मिला है। रिपोर्ट के अनुसार 18-24 जून में मौत के सबसे अधिक 69 मामले सामने आए। हाल के सप्ताहों में मेक्सिको के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार तक पहुंच गया था। 11 से 17 जून के बीच देश में गर्मी से मौत के 31 मामले सामने आए। इस साल अभी लू लगने और पानी की कमी के कारण उत्तरी सीमावर्ती राज्य नुएवो लियोन में सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति एंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि गर्मी से मौत के मामलों से जुड़ी खबरें झूठी हैं और यह उनके प्रशासन के खिलाफ मीडिया के अभियान का हिस्सा है।

कनाडा के जंगलों में लगी आग के धुएं से 120 मिलियन अमेरिकी प्रभावित

लॉस एंजिल्स । कनाडा के जंगलों में लगी आग से निकले धुएं के कारण मध्य पश्चिम से पूर्वी तट तक एक दर्जन से अधिक अमेरिकी राज्यों में 120 मिलियन से अधिक लोग वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। कैनेडियन इंटरएजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर के अनुसार कनाडा में सैकड़ों जगहों पर आग लगी हैं। इनमें से 250 से अधिक स?थानों पर तो यह नियंत्रण से बाहर है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस (एनडब्ल्यूएस) के अनुसार धुएं को देखते हुए न्यूयॉर्क, आयोवा, विस्कॉन्सिन, इलिनोइस, इंडियाना, मिशिगन, डेलावेयर और मैरीलैंड सहित एक दर्जन से अधिक अमेरिकी राज्यों में वायु प्रदूषण संबंधी अलर्ट जारी किया गया है। आईक्यू एयर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार गुरुवार सुबह तक वाशिंगटन डी.सी. शिकागो और डेट्रॉइट दुनिया में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में से थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की एक तिहाई से अधिक आबादी वायु गुणवत्ता अलर्ट के अधीन है, इसके कुछ ही सप्ताह बाद पूर्वोत्तर में इसी तरह की जंगल की आग का धुआं छा जाने के बाद अधिकारियों ने जनता से सुरक्षा सावधानी बरतने का आह्वान किया है। एनडब्ल्यूएस ने चेतावनी दी है कि कनाडा के जंगल की आग का कोई अंत नहीं दिख रहा है, इसलिए खराब वायु गुणवत्ता जारी रहने की संभावना है। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों को चिंता है कि धुआं यात्रा में बाधा डाल सकता है और 4 जुलाई की छुट्टियों के दौरान अमेरिकियों के लिए उड़ान में देरी और रद्दीकरण हो सकता है। कनाडा के जंगल की आग के धुएं के कारण सुदूर यूरोप तक आसमान में धुंध छाई हुई है। यूएस सीडीसी के अनुसार जंगल की आग का धुआं और राख आंखों, नाक, गले और फेफड़ों में जलन पैदा कर सकता है, इससे लोगों को खांसी या घरघराहट हो सकती है और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। जंगल की आग के धुएं से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका घर के अंदर रहना या बाहर समय सीमित करना है। यह हृदय या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों के लिए अधिक नुकसानदेह है।

ट्रंप ने बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला पर मुकदमा दर्ज कराया

न्यूयॉर्क । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला पर जवाबी मुकदमा दायर कर दावा किया है कि शिकायकर्ता पर उनके पैसे बकाया है, इतना ही नहीं जूरी द्वारा इनकार करने के बाद भी वह उन्हें बदनाम करने के लिए बलात्कार करने का आरोप लगाती रही है। मैनहट्टन फैडरल ज्यूरी ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को स्तंभकार ई.जीन कैरल का यौन उत्पीड़न और उनकी मानहानि करने का दोषी पाया था। अदालत ने ट्रंप पर 50 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया था। हालांकि, अदालत ने कहा था कि कैरल यह साबित करने में विफल रहीं कि ट्रंप ने उनके साथ बलात्कार किया था। कैरल ने आरोप लगाया था कि पूर्व राष्ट्रपति ने मैनहैट्टन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उनसे दुष्कर्म किया था। ट्रंप के वकील ने मुकदमा दाखिल कर कहा कि कैरोल को ट्रंप को दंडात्मक क्षतिपूर्ति का भुगतान करना चाहिए और अपने मानहानिकारक बयानों को वापस लेना चाहिए। गौरतलब है कि ट्रंप ने अलग-अलग महिलाओं द्वारा खुद पर लगाए गए यौन उत्पीड़न और यौन दुर्व्यवहार के आरोपों को लगातार खारिज किया है। उनका दावा है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और उनकी छवि खराब करने की साजिश हैं, ताकि वह व्हाइट हाउस की दौड़ में न शामिल हो सके।

बढ़ते तापमान से तबाह हो जाएगी धरती, वैज्ञानिक हो रहे चिंतित

-खगोलविदों का अनुमान, यह सब 2025 से पहले होगा घटित

लंदन। बढ़ते तापमान से दुनिया के खगोलविद चिंतित हो रहे हैं। उनका अनुमान है कि बढ़ते तापमान से धरती तबाह हो जाएगी और यह सब 2025 से पहले ही घटित हो सकता है। इसलिए दुनिया भर में बढ़ते तापमान को लेकर वैज्ञानिक व खगोलविद चिंतित हैं। कई सारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले वर्षों में दुनिया भर का तापमान बढ़ने वाला है। ऐसे में एक और खबर ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल, सूर्य में सोलर एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। जबकि खगोलविदों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा 2025 से पहले होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस साल के अंत तक सूर्य का अधिकतम तापमान बढ़ने की उम्मीद है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक, एलेक्स जेम्स ने बताया कि सूर्य का तापमान समय से पहले चरम पर पहुंचने वाला है और अपेक्षा से अधिक इसका तापमान होगा। सौर ऊर्जा बढ़ने से पृथ्वी पर कई गंभी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर अधिकतम के दौरान, सूर्य पर चुंबकीय क्षेत्र अपने सबसे निचले स्तर पर होता है, जो पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल के रूप में कार्य करता है जो सौर विकिरण को रोकता है और सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) को भी रोकता है। नासा के मुताबिक सनस्पॉट वे क्षेत्र हैं, जो सूर्य की सतह पर काले रंग के दिखाई देते हैं। वे काले रंग के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे सूर्य की सतह के अन्य हिस्सों की तुलना में ठंडे हैं। सूर्य के धब्बों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पुनर्गठित होने पर विस्फोट का कारण बनती हैं, जिससे सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। यह अंतरिक्ष में बहुत सारा विकिरण छोड़ता है। नासा ने कहा कि विस्फोट से विकिरण निकलता है जो पृथ्वी पर हमारे रेडियो संचार में हस्तक्षेप कर सकता है।

तुर्केमिनिस्तान में लोग नये शहर की शुरुआत के अवसर पर पहुंचे। यह शहर देश के पूर्व राष्ट्रपति कुरबांगुली बरडियोमुखमदेव को समर्पित किया गया है।

रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया महान मित्र

मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का अच्छा मित्र कहा और भारत की मेक इन इंडिया पहल की भी प्रशंसा की। मॉस्को में एजेंसी फॉर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स (एएसआई) द्वारा आयोजित एक आर्थिक मंच से राष्ट्रपति ने कहा ?कि भारत में हमारे मित्र और हमारे बड़े मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साल पहले मेक इन इंडिया पहल शुरू की थी। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर वास्तव में बड़ा प्रभाव पड़ा है। पुतिन ने पश्चिमी देशों की प्रतिबंध लगाने की नीति को रूसी कंपनियों के लिए अवसर बताया और कहा कि हमारी कंपनियों को अपने उत्पाद अधिक कुशलता से विपणन करने में इस नीति से मदद मिलती है। औद्योगिक और उत्पाद डिजाइन घरेलू व्यापार के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनना चाहिए। मेक इन इंडिया पहल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश में बने उत्पादों को विकसित करने, निर्माण करने और इकट्ठा करने के लिए कंपनियों को बनाना और प्रोत्साहित करना और विनिर्माण में समर्पित निवेश को प्रोत्साहित करना था। पुतिन और मोदी की आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में एक क्षेत्रीय सुरक्षा ब्लॉक शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई थी।

फ्रांस में तीसरे दिन भी जारी हैं हिंसक प्रदर्शन

शूटआउट पर सवाल, पेरिस में भीषण बवाल, दंगों के कहर से छावनी में तब्दील हुआ पूरा शहर

पेरिस (एजेंसी)। फ्रांस में पुलिस द्वारा 17 साल के एक लड़के की गोली मारकर हत्या करने के मामले में देश भर में हिंसक प्रदर्शन जारी है। अभी तक 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में गृह मंत्री गेराल्ड डर्मैनिन के हवाले से बताया कि गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक विरोध प्रदर्शन में कम से कम 421 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से आधे से अधिक गिरफ्तारियां पेरिस क्षेत्र में हुईं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन गुरुवार को लगातार तीसरे दिन जारी रहा। हिंसा रोकने में मदद के लिए विशेष पुलिस बल को बोर्डो, ल्योन, रूबैक्स, मार्सेल और लिली शहरों में तैनात किया गया। पेरिस के एक उपनगर नानटेयर में नाहेल एम. को एक पुलिस अधिकारी ने गोली मार दी थी। नाहेल ने ट्रैफिक पुलिस पर रुकने से इनकार कर दिया था और गाड़ी चला कर भागने लगा, जब पुलिस ने गोली मारी। प्राप्त फुटेज के अनुसार, जलते हुए मलबे के बीच, नैनटेयर में एक दीवार पर नाहेल के लिए बदला पेंट किया हुआ दिखाई दिया।

उपनगर में एक बैंक में भी आग लगा दी गई और लड़के की याद में आयोजित मार्च के हिंसक हो जाने के बाद पुलिस ने 15 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि मार्सेल में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस

अधिकारियों पर बम फेंके। लिली के वीडियो में सड़कों पर आग जलती हुई और दंगा करने वाले पुलिस अधिकारियों को भागते हुए देखा गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी ने कहा कि लिली में अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद छह लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया गया।

लिली में बसें और ट्रामवे रात 8 बजे के बाद बंद कर दिए गए, जबकि पेरिस के कई उपनगरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। गुरुवार रात से ही पेरिस के कई हिस्सों में बस और ट्राम सेवाएं निलंबित कर दी गईं। इस बीच, गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने पेरिस में 5,000 सहित देश भर में 40,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात करने की योजना बनाई है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने दावा किया कि जब पहली बार दंगा भड़का तब 40 कारें जला दी गईं और झड़पों में 24 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। नाहेल इस साल फ्रांस में ट्रैफिक रोकने के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारा जाने वाला दूसरा व्यक्ति है। पिछले साल इस तरह से रिकॉर्ड 13 लोगों की मौत हुई थी।

भूल गया भारत के एहसान.. श्रीलंकाई विदेश कर रहे चीन का गुणगान

कोलंबो (एजेंसी)। चीनी कर्ज के तले दबा श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बाद फिर से पटरी पर लौट रहा है। श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे गति पकड़ रही है, उसके सुर बदल रहे हैं। दरअसल श्रीलंका के डिफॉल्ट होने के दौरान भारत ने खाने पीने के सामान से लेकर अरबों डॉलर की मदद दी थी। अब श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी चीन पहुंचे हैं। जहां उन्होंने कहा है कि भारत-चीन प्रतिस्पर्द्धा में उनका देश तटस्थ रहेगा। यह वहीं चीन है जिसके बेल्ट एंड रोड कर्ज ने श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। अब श्रीलंका फिर से चीन के गुणगान करने लगा है।

श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने भारत-चीन को नसीहत देकर कहा कि यह दोनों देशों और दुनिया के लिए अच?छा होगा कि वे अपने मतभेदों को कम करें। साबरी ने कहा कि भारत बनाम चीन होने पर वह किसी का पक्ष नहीं लेने वाले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका देश भारत और चीन को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के तनाव में कई क्षेत्रीय देशों के फंसने का खतरा है। साबरी ने चीनी मीडिया से कहा, हम चाहते हैं कि भारत और चीन एक-दूसरे से बातचीत करें तथा अपने मतभेदों को दूर करें। यह दोनों देशों और दुनिया के लिए बेहतर होगा।

गलवान घाटी में चीन की खूनी हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बहुत गंभीर हो गया है। दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक आमने-सामने हैं।

चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अली साबरी ने श्रीलंकाई दूतावास में कहा, हमने चीन और भारत दोनों को ही यह साफ कह दिया है कि हम बिजनस के लिए किसी के साथ तैयार हैं लेकिन एक-दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाएंगे। उनका यह बयान उस समय पर आया है जब श्रीलंका चीन से कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए गुहार लगा रहा है लेकिन ड्रैगन अभी इधर-उधर कर रहा है। श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का 10 प्रतिशत चीन का है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन की कोशिश श्रीलंका को कर्ज जाल में फंसाकर रखने की है।

विश्लेषकों के मुताबिक श्रीलंका की बदहाली के अभी एक साल भी नहीं बीते हैं और उसके सुर बदल गए हैं। अली साबरी ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। इस दौरान श्रीलंका ने वचन दिया है कि वह देश में बीआरआई प्रॉजेक्ट की सफलता को सुनिश्चित करेगा। साथ ही साबरी ने यह भी कहा कि श्रीलंका एक चीन नीति का पालन करता रहेगा।

नए परिसीमन के आधार पर नहीं होंगे आम चुनाव, परिणाम अभी तक नहीं हुए अधिसूचित

इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डिजिटल जनगणना के नतीजों को अभी तक पाकिस्तान में औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए नवीनतम परिसीमन के आधार पर आगामी आम चुनाव कराना सवाल से बाहर है। डॉन ने अधिकारी के हवाले से कहा कि राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2023 आयोग द्वारा पिछले साल 5 अगस्त को प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। यह टिप्पणी 8 जुलाई को शुरू होने वाले गणना के बाद के सर्वेक्षण से पहले आई है, जिसके तहत 31 जुलाई तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस सबके बीच, विभिन्न संघीय मंत्रियों ने दावा किया है कि आगामी चुनाव नए परिसीमन अभ्यास से पहले होंगे।

अमेरिका से भारत को उन्नत सैन्य हथियारों का हस्तांतरण पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा

-अमेरिका को बताया अपना डर

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने गहरे रक्षा सहयोग पर अमेरिका को अपनी कड़ी आपत्ति जताकर पाकिस्तान की सुरक्षा हितों के लिए सीधा खतरा माना है। रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने कहा कि अमेरिका को राजनयिक चैनलों के माध्यम से सूचित किया गया था कि पाकिस्तान की वैध चिंताओं को ध्यान में रखे बिना भारत को उन्नत सैन्य हथियारों का हस्तांतरण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता और पारंपरिक संतुलन को कमजोर कर देगा। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि भारत प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण से उत्साहित महसूस करेगा, इससे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हित खतरे में पड़ जाएंगे।

इस्लामाबाद ने वाशिंगटन को स्पष्ट किया हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसा सहयोग जो उसके हितों को नुकसान करेगा, पाकिस्तान के पास जवाबी कदम उठाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत लड़ाकू जेट इंजन भारत में बनाएगी। अमेरिका युद्ध-परीक्षणित सशस्त्र ड्रोन के उत्पादन के लिए भारत में एक इकाई स्थापित करने पर भी सहमत हुआ। दशकों तक, रूस 65 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत को हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना रहा।

कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान को आईएमएफ से मिली तीन अरब डॉलर की मदद

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिन्होंने पिछले दिनों पेरिस जाकर मदद की गुहार लगाई थी, उनकी अपील आखिरकार काम आ गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की ओर से पाकिस्तान के साथ एक स्टैंडबाय एग्रीमेंट किया गया है। समझौते के बाद पाकिस्तान को तीन अरब डॉलर की मदद मिलेगी। आईएमएफ के कार्यकारी अधिकारी नाथन पोर्टर की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। आईएमएफ ने तीन जुलाई 2019 को पाकिस्तान के लिए 21वें ऋण की मंजूरी दी थी। यह कार्यक्रम 30 जून को खत्म हो रहा था। इसके बाद पाकिस्तान पर कंगाल होने का खतरा टल गया है।

तीन अरब डॉलर वाले इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट स्टैंडबाय एग्रीमेंट को आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। पाकिस्तान जो डिफॉल्ट होने की

कगार पर था, यह ऐलान उसके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। देश वर्तमान में गंभीर भुगतान संतुलन संकट और गिरते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। आईएमएफ के अधिकारी पोर्टर ने कहा, नया स्टैंडबाय समझौता पाकिस्तान के 2019 विस्तारित फंड सुविधा-समर्थित कार्यक्रम पर आधारित है जो जून के अंत में खत्म हो रहा है। आईएमएफ बोर्ड की एक मीटिंग जुलाई में होनी है और इसी मीटिंग में पता चलेगा कि डील को मंजूरी मिलेगी है या नहीं।

तीन अरब डॉलर की फंडिंग जो नौ महीने से ज?यादा समय की है, पाकिस?तान के लिए बड़ी राहत है। साल 2019 में 6.5 अरब डॉलर वाले कर्ज प्रोग्राम को मंजूरी मिली थी। अब इसमें से 2.5 अरब डॉलर की राशि मिलनी बाकी है। आईएमएफ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हाल के दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों में पिछले साल विनाशकारी बाढ़ और यूक्रेन में युद्ध के बाद जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल है। उन्होंने कहा आयात और व्यापार घाटे को कम करने के अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद, भंडार बहुत निचले स्तर तक गिर गया। इन चुनौतियों को देखते हुए, नई व्यवस्था आने वाले समय में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय भागीदारों से वित्तीय सहायता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी।

कभी अमेरिका दौरे पर आतंकवाद पर चर्चा होती थी, मोदी ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए: नड्डा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि में बड़ा बदलाव आया है और भारत के प्रधानमंत्री अब अमेरिकी दौरे के दौरान सीमा पार आतंकवाद के बारे में बात नहीं करते हैं, जैसा पहले के प्रधानमंत्री किया करते थे। नड्डा ने कहा, ''पहले जब भी अंतरराष्ट्रीय नेता भारत के बारे में चर्चा करते थे तो वह भारत और पाकिस्तान को एक साथ रख देते थे, लेकिन अब जब भारत की बात होती है तो कोई पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता।'' भरतपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वंशवाद की राजनीति पर भी विपक्षी दलों पर हमला किया और कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पार्टी एक परिवार है जबकि अन्य सभी दल परिवार की पार्टी बन गए हैं। भाजपा प्रमुख ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण भारत की गरीबी 22 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गई है और अत्यधिक गरीबी एक फीसदी से भी कम हो गई है।

नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो सीमा पार आतंकवाद पर चर्चा करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। भाजपा नेता ने भरतपुर जिले में अपने संबोधन में कहा, ''आज हमारे समझौते होते हैं तो अंतरिक्ष, क्रायोजेनिक इंजन, विदेशी निवेश (एफडीआई) पर समझौता है और एक दूसरे को तकनीकी सहायता देने पर भी समझौता होता है।'' उन्होंने कहा, ''आतंकवाद की बात हम नहीं करते, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित रख कर चलाने की हमने सामर्थ्य पैदा कर ली है और हम आगे बढ़ रहे है।'' उन्होंने कहा, ''2014 के पहले जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता भारत के बारे में चर्चा करता था तो हमेशा कहता था 'इंडिया एंड पाकिस्तान' मतलब हमको दोनों को साथ रख करके ज यह लड़ने वाले दो देश हैं। यह इंडिया एडं पाकिस्तान इस तरीके से हमारे को अंतर्राष्ट्रीय में, हमारे बारे में सम्बोधन होता था।

2014 में मोदी के आने के बाद भारत की चर्चा जब होती है..पाकिस्तान गौंण हो गया है, कोई चर्चा नहीं करता और भारत से जोड़ना समाप्त हो गया।'' उन्होंने कहा, ''हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने एक नया राजनीतिक आयाम शुरू किया। दुनिया में, देश में सारी पार्टियांज्परिवार ही उनकी पार्टी बन गयी और यह भाजपा अकेली पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है। यह अंतर हमको समझना है बाकि सब पार्टियां परिवार की पार्टी बन गयी है, कोई बचा नहीं है।'' उन्होंने कहा '' भाजपा अकेली पार्टी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने वंशवाद को चुनौती देकर रिपोर्ट कार्ड की राजनीती को खड़ा किया और जनता के लिए काम करने के लिए जुटे। वोट बैंक की राजनीती को समाप्त करके विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है।'' उन्होंने कहा, ''जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी फारूख अब्दुला के परिवार की पार्टी, मुफ़्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ़्ती परिवार की पार्टी, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी, हरियाणा में परिवार की पार्टी, 24 करोड़ लोगों का प्रदेश उत्तर प्रदेश किस से लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी से जो परिवार की पार्टी है, बिहार में हमारी लड़ाई है आरजेडी से, कौन हैं लालू यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव फलाना यादव, परिवार की पार्टी।''

नड्डा ने कहा,''बंगाल में हम किस से लड़ रहे हैं टीएमसी ज ममता बनर्जी और उनका भतीजा अभिषेक परिवार की पार्टी, बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस भी परिवार की पार्टी, चंद्रशेखर राव परिवार की पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके स्टालिन परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना परिवार की पार्टी..ये सब परिवार की पार्टियां हैं।'' उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी भी अब मां बेटी, बेटा की पार्टी बन गयी है। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से सर्वाधिक बजट आवंटन के बावजूद राजस्थान जल जीवन मिशन में प्रदर्शन में 29वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राजस्थान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में लाने का आग्रह किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान अग्रणी राज्य है। रैली को संबोधित करने से पहले पार्टी अध्यक्ष ने भरतपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी के भरतपुर कार्यालय में एक पुस्तकालय की स्थापना करने करने और भरतपुर का इतिहास उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

6 साल का हुआ जीएसटी, अब तक 3,00,000 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी

नई दिल्ली । देश में कर की चोरी और टैक्स पर नियंत्रण करने के लिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी। जीएसटी का पूरा नाम माल एवं सेवा कर है। इस अप्रत्यक्ष कर में सुधार के तहत लाया गया है। शुरुआती दौर में देश में केवल 85,000-95,000 करोड़ रुपये का ही जीएसटी कलेक्शन होता था। वहीं, अप्रैल, 2023 में ये कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये अभी तक का सबसे उच्च स्तर है। देश में इतनी बड़ी संख्या में जीएसटी संग्रह करने में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक महीने में 11,140 जीएसटी फर्जी के मामले पकड़े हैं। इन मामलों से 15,000 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। जीएसटी परिषद ने 2016 से अब तक 3,00,000 करोड़ रुपये के टैक्स चोरी के मामले पकड़े हैं। परिषद का अनुमान है कि जुलाई 2017 में 3 लाख करोड़ रुपये की टैक्स चोरी हुई है। टैक्स चोरी को नियंत्रण करने के लिए जीएसटी काफी कारगर साबित हुआ है। कर धोखाधड़ी को रोकने के लिए कर अधिकारी कई नए तरीके को आजमा रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के बाद फर्जी कंपनियां बनाने वालों के लिए जीएसटी अधिकारियों ने डेटा विश्लेषण, एआई और मशीन लर्निंग उपयोग करना शुरू कर दिया है। जीएसटी द्वारा आईटीसी के फर्जी दावों को रोका जा सकता है। वहीं जीएसटी की दरों को पूरे देश में एक समान बनाने के लिए पेट्रोल, डीजल एवं विमान ईंधन पर जीएसटी लगाने की जरूरत है। इसी के साथ ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो लेनदेन, ईवी चार्जिंग ढांचे पर भी जीएसटी दरों पर फैसले लेने की जरूरत है।

इंदौर में स्कूल वैन में आग लगी, बीएसएफ जवानों ने चालक और बच्चों की जान बचाई

इंदौर (मध्यप्रदेश)। मप्र के इंदौर में शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया, जब छह बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन में लगी आग को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों की मदद से बुझा लिया गया, इस वाहन का चालक और सभी छह बच्चे सुरक्षित हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आदित्य मिश्रा ने बताया कि एयरोड्रम थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय की वैन में संभवत- शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उन्होंने बताया कि यह हादसा बीएसएफ के केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय (सीएसडब्ल्यूटी) के परिसर के सामने हुआ। डीसीपी ने बताया,''बीएसएफ जवानों ने जलती वैन से इसके चालक और छह बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग बुझानी शुरू की।'' मिश्रा ने बताया कि अग्निकांड की सूचना मिलने पर अग्निशमन दस्ता भी मौके पर पहुंचा और आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। डीसीपी ने बताया,''स्कूल वैन में लगी आग पर समय रहते काबू पाए जाने से बड़ा हादसा होते-होते टल गया है। हम एहतियात के तौर पर शहर के सभी स्कूल वाहनों के रख-रखाव की स्थिति जांचेंगे ताकि आइंदा ऐसे अग्निकांड नहीं हो सकें।

दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर इसके दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने इनके पास से आठ करोड़ रूपये मूल्य की हेरोइन और ट्रैमाडोल पाउडर भी जब्त किया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपियों की पहचान झारखंड के चतरा निवासीधर्मेंद्र कुमार (26) और विशेश्वर यादव (40) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके पास से 1.505 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाली हेरोइन और 2.216 किलोग्राम ट्रैमाडोल पाउडर जब्त किया है। विशेष पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल ने बताया कि 23 जून को पुलिस को सूचना मिली कि धर्मेंद्र कुमार अपने अन्य सहयोगियों के साथ कुछ लोगों को मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप देने के लिए सराय काले खां आएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों ने मादक पदार्थ तस्कर होने और अपने साथ हेरोइन और ट्रैमाडोल ले जाने की बात स्वीकार की। उन्होंने आगे बताया कि वे इस गिरोह के सरगना दिनेश यादव के निर्देश पर मादक पदार्थों की आपूर्ति कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दिनेश यादव को पकड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।

चंद्रयान-3 की लांचिंग पर इसरो प्रमुख....अभी डेट फाइनल नहीं

-12 से 19 जुलाई के बीच हो सकती हैं लांचिंग

नई दिल्ली । चंद्रयान-3 को 13 जुलाई को प्रक्षेपित करने की संभावना है, जिसके द्वारा चंद्रमा की सतह पर एक 'रोवर उतारा जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 13 जुलाई को दोपहर ढाई बजे प्रक्षेपित किया जाएगा। हालांकि, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इसकी तिथि पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है, यह 12 से 19 जुलाई के बीच की तिथि पर विचार हो रहा है। उन्होंने 13 जुलाई की प्रक्षेपण तिथि के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देकर कहा,''अभी, 12 से 19 जुलाई के बीच (किसी तिथि) के विकल्प को खुला रखा गया है। यह 12, 13 या 14 जुलाई हो सकता है या अंत (19 जुलाई) तक जा सकता है, बशर्ते कि कोई तकनीकी समस्या न पैदा हो। सोमनाथ ने कहा,''कोई सटीक तिथि घोषित नहीं की गई है। हम सभी जांच पूरी होने के बाद उस सटीक तिथि पर पहुंचेंगे...अंतिम तिथि इस रेंज के अंदर होगी। इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान पूरी तरह से तैयार है। सोमनाथ ने कहा,''अभी रॉकेट के साथ इस जोड़ा जा रहा है तथा संभवत- यह कार्य और दो-तीन दिन में पूरा हो जाएगा, फिर हमें जांच कार्यक्रम में जाना है। उन्होंने कहा कि रॉकेट से जोड़े जाने के बाद सिलसिलेवार जांच भी की जाएगी। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने और वहां गतिविधियां करने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान-2 के बाद का यह एक अभियान है। चंद्रयान-3 के जरिए एक 'लैंडर और एक 'रोवर को चंद्रमा पर भेजा जा रहा है। प्रणोदन मॉड्यूल, 'लैंडर और 'रोवर को 100 किलोमीटर तक चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा।

जोशीमठ के बाद उत्तरकाशी के गांवों में घरों में आई दरार, लोगों में हड़कंप

उत्तरकाशी । उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब उत्तरकाशी के गांवों में घर की दीवारों पर दरारें नजर आ रही हैं। मस्तादी गांव के निवासियों में उस समय हड़कंप की स्थिति मच गई, जब उन्हें घर की दीवारों पर दरार नजर आई।बताया जा रहा हैं कि भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से ऐसा हुआ है। उत्तरकाशी जिले के घरों में दरार वाले गांव के प्रधान सत्यनारायण सेमवाल ने बताया कि साल 1991 में आए भूकंप के बाद से इलाके में जमीन के खिसकने की शुरुआत हो गई थी। उन्होंने बताया कि यहां के कई घरों में ताजा दरारें पड़ी नजर आई हैं। हमें चिंता है कि अब आगे कौन सी मुसीबत देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में कोई एक्शन लेना चाहिए। कम से कम जिन 30 के करीब घरों में दरारें नजर आई हैं, वहां रह रहे परिवारों को विस्थापित करना चाहिए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि प्रभावित इलाकों के सर्वे के लिए भूविज्ञानियों की टीम को भेजा जाएगा। जानकारों की सलाह पर जरूरी एक्शन लिया जाएगा। भूविज्ञानियों की एक टीम ने 1997 में गांव का सर्वे करने के बाद जमीन के खिसकने को लेकर तत्काल कदम उठाने की सलाह दी थी। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि समस्या के निदान की दिशा में कोई भी प्रभावी कदम आज तक नहीं उठाया गया। जमीन खिसकने और दरारें पड़ने के अलावा नारायणपुरी और त्रिपकुंड मंदिरों के बीच अलकनंदा नदी के पास रहने वाले लोगों को भूस्खलन का भी डर सता रहा है। निवासियों का कहना है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत जारी रिवरफ्रंट कार्य की वजह से ऐसा खतरा मंडरा रहा है।

भीम आर्मी के चीफ आजाद को जान से मरने की धमकी, युवक गिरफ्तार

अमेठी । भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को कथित तौर पर 'क्षत्रिय ऑफ अमेठी' नाम के फेसबुक पेज पर जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल, सहारनपुर जिले के देवबंद में आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वह घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई कार सहारनपुर जिले के मिरगपुर गांव से बरामद कर ली गई है।

राजनीति विज्ञान की डिग्री ने संवेदनशीलता नहीं सिखाई

मणिपुर की स्थिति को लेकर पीएम मोदी पर जयराम रमेश ने साधा निशाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में उल्लेखनीय प्रवेश किया और परिवहन के अपने पसंदीदा साधन के रूप में मेट्रो की सवारी को चुना। जहां प्रधानमंत्री की यात्रा के विकल्प ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और पीएम के इस मूव की प्रशंसा भी गई। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी आलोचना भी करते हुए प्रधानमंत्री पर मणिपुर की स्थिति के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।

अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की मेट्रो यात्रा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास उस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए मेट्रो में यात्रा करने का समय और झुकाव है, जिसने उन्हें %संपूर्ण राजनीति विज्ञान% में एमए की डिग्री दी, जिसने स्पष्ट रूप से उन्हें यह नहीं सिखाया कि कैसे परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी का मेट्रो लेने का निर्णय दिल्ली-एनसीआर में आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की उनकी पिछली प्रथाओं के अनुरूप था। प्रधानमंत्री की मेट्रो यात्रा ने उन्हें यात्रियों के साथ बातचीत करने और परिवहन के इस लोकप्रिय साधन की सुविधा का अनुभव करने का अवसर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच, पीएम मोदी दिन में दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और शताब्दी समारोह में सभा को संबोधित किया। प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय के महत्व के बारे में बोलते हुए, प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डीयू सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है बल्कि अपने आप में एक आंदोलन है।

ललन सिंह का शाह पर तंज, इतना घबराना देश के गृहमंत्री के लिए ठीक नहीं

पटना (ईएमएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे पर लखीसराय में जनसभा को संबोधित कर विरोधियों पर जमकर सियासी हमला किया। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री शाह पर पलटवार कर उन्हें झूठा तक कह दिया। उन्होंने गृह मंत्री को नसीहत देकर कहा कि इतना घबराना ठीक नहीं है। ललन सिंह ने ट्वीट कर शाह को चुनौती देकर कहा कि साबित करे कि मुंगेर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलवाने में केंद्र सरकार का एक रुपया भी लगा है। उन्होंने दावों के साथ कहा कि मुंगेर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नीतीश सरकार की योजना का प्रतिफल है और इसमें शत-प्रतिशत राज्य सरकार का रुपया लगा है। इसमें केंद्र सरकार का एक रुपया भी नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की उपलब्धि भी नरेंद्र मोदी के नाम करने का साहस कोई झूठा व्यक्ति ही कर सकता है। जदयू नेता ने कहा कि साहस है, तब बताइए कि हर घर नल का जल योजना में केंद्र सरकार का कितना रुपया लगा है? इस योजना के लिए केंद्र सरकार के ऑफर को नीतीश सरकार ने ठुकराया और एक रुपया भी नहीं लिया। अपने धन से राज्य सरकार ने 2015 में सात निश्चय योजना के तहत इस बिहार में करवाया। मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाला पुल नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की देन है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा कि शायद आज आप अधिक तनाव में थे, इसलिए नीतीश सरकार की उपलब्धियों को भी अपने खाता में डाल रहे थे। ऐसा आप ही कर सकते हैं और यही देश के साथ भी कर रहे हैं। सिंह ने शाह से पूछा कि आज आप इतने घबराए हुए क्यों थे कि लगातार आपके मुंह से लखीसराय की जगह मुंगेर निकल रहा था? माना कि आपको आम चुनाव में अपने हश्र का अंदाजा है, लेकिन इतना घबराना देश के गृह मंत्री के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।

यूसीसी पर सक्रिय हुई मोदी सरकार, स्थायी समिति ने 3 जुलाई को बुलाई बैठक

-मानसून सत्र में हो सकता हैं बिल पेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इनदिनों देश भर में चल रही चर्चा के बीच कयास लग रहे हैं कि संसद के मानसून सत्र में यूसीसी संबंधित बिल पेश हो सकता है। मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होने की बात हो रही है। हालांकि अभी तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मोदी सरकार मामले पर सभी पक्षकारों से बातचीत के पक्ष में है। लॉ कमीशन ने भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस बीच संसद की कानून मामलों की स्थायी समिति ने भी 3 जुलाई को एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है।

जाहिर है कि चुनावी साल में विपक्ष अपने मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तब सरकार यूसीसी जैसे अहम विषय पर विपक्ष की घेराबंदी की कोशिश करेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। इसके बाद से फिर देश की राजनीति में यूसीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यूसीसी का जिक्र करके देश के लोगों को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। संसद की स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के विचार लेने के लिए विधि आयोग द्वारा हाल में जारी नोटिस पर तीन जुलाई को (विधि) आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है। विधि और कार्मिक मामलों पर स्थायी समिति के कार्यक्रम के अनुसार, वह 'पर्सनल लॉ की समीक्षा' विषय के तहत यूसीसी पर विभिन्न हितधारकों की राय लेने के लिए 14 जून 2023 को विधि आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस पर कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों और विधायी विभागों तथा कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुनेगी। मंगलवार शाम तक विधि आयोग को अपने सार्वजनिक नोटिस पर करीब 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिली थीं।

एससीओ की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे शी जिनपिंग

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले सप्ताह भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने घोषणा की है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेने वाले हैं।

एससीओ द्वारा जारी बयान के अनुसार राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल एससीओ परिषद 4 जुलाई को आयोजित होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। शिखर सम्मेलन का विषय एक सिक्योर एससीओ की ओर है। सिक्योर का संक्षिप्त नाम प्रधानमंत्री द्वारा 2018 एससीओ शिखर सम्मेलन में गढ़ा गया था और इसका अर्थ सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण है।

एससीओ प्रोटोकॉल के अनुपालन में तुर्कमेनिस्तान को अध्यक्ष के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दो एससीओ निकायों अर्थात् सचिवालय और एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) के प्रमुख उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र (यूएन), आसियान, सीआईएस, सीएसटीओ, ईएईयू और सीआईसीए सहित छह अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के नेताओं को भी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। भारत ने अपनी अध्यक्षता में सहयोग के स्टार्टअप और इनोवेशन, पारंपरिक औषधि, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तिकरण और साझा बौद्ध विरासतनए स्तंभ स्थापित किए हैं। इसके अलावा, भारत ने लोगों के बीच व्यापक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। बयान में कहा गया है कि इनमें 2022-23 के लिए पहली एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के ढांचे के तहत वाराणसी द्वारा आयोजित विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं।

एससीओ में भारत की अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच गहन गतिविधि और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का काल रहा है। भारत ने कुल 134 बैठकों और कार्यक्रमों की मेजबानी की है, जिनमें 14 मंत्री-स्तरीय बैठकें शामिल हैं। भारत संगठन में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी अध्यक्षता की परिणति के रूप में एक सफल एससीओ शिखर सम्मेलन की आशा करता है।

दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां जलाकर विरोध, बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी 'आप'

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) केंद्र सरकार के दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां जलाकर उसके खिलाफ 3 जुलाई से चरणबद्ध अभियान चलाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। केंद्र ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए 19 मई को एक अध्यादेश लाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपने के कुछ दिनों बाद यह अध्यादेश जारी किया गया था। इसके बाद, अरविंद केजरीवाल समर्थन जुटाने के लिए देश भर में विभिन्न विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अध्यादेश देश के संघीय ढांचे को नष्ट कर देगा। हालांकि कई गैर-भाजपा दलों ने अध्यादेश पर आप का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे की निंदा नहीं की है। 23 जून को पटना में विपक्ष के हंगामे के दौरान, अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को बैठक के दौरान उठाने पर जोर दिया था, लेकिन यह राजनीतिक विवाद में बदल गया। सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तब आप और कांग्रेस से दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर अपने मतभेदों को बाद में चाय और बिस्कुट पर सुलझाने के लिए कहा, और उन्हें याद दिलाया कि पटना विपक्ष की बैठक इस तरह की चर्चा के लिए आदर्श मंच नहीं थी। विधेयक को

संसद में विचार के लिए लाए जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल इस पर विधायी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। जबकि लोकसभा में परिणाम पहले से तय था, राज्यसभा में विधेयक को हराने का मौका अभी भी एक खुला खेल है।

मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मिले राहुल गांधी

-लोगों की दुर्दशा को देखना और सुनना दिल दुखने वाला

पटना (एजेंसी)। इंफाल (ईएमएस)। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने इंफाल में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा के कारण अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों की दुर्दशा को देखना और सुनना दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा कि वहां मदद की गुहार लगाई जा रही है और पूर्वोत्तर राज्य को जीवन और आजीविका सुरक्षित करने के लिए शांति की जरूरत है।

राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर में हिंसा के कारण जिन लोगों ने अपने प्रियजनों और घरों को खो दिया है, उनकी दुर्दशा को देखना और सुनना दिल दहला देने वाला है। हर भाई, बहन के चेहरे पर मदद की पुकार है।

दरअसल राहुल गांधी गुरुवार सुबह मणिपुर पहुंचे थे। इसके बाद चुराचांदपुर और पश्चिम इंफाल में राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी। गुरुवार को राहुल गांधी के काफिले को बिष्णुपुर इलाके में रोक दिया गया, इसके बाद उन्हें इंफाल लौटना पड़ा। इसके बाद वह चुराचांदपुर राहत शिविर तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर से गए। गौरतलब है कि मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़क उठी थी और तब से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, जो राहत शिविरों में हैं।

समान नागरिक संहिता के लिए केंद्र का समर्थन करेगी उद्धव सेना!

नोएडा (एजेंसी)। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका जिक्र किए जाने के बाद से राजनीति दलों की ओर से इसके समर्थन और विरोध में अपनी-अपनी दलीलें दी जा रही हैं। इन सब के बीच संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के विचार लेने के लिए विधि आयोग द्वारा हाल में जारी नोटिस पर तीन जुलाई को (विधि) आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है। वहीं सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उद्धव

ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए केंद्र सरकार के दबाव का समर्थन करेगी। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि पार्टी की सोच हमेशा यूसीसी की रही है लेकिन अंतिम निर्णय मसौदा तैयार होने के बाद किया जाएगा।

लॉ कमीशन की ओर से यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और जनता से राय मांगी गई थी। लॉ कमीशन के कदम के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने भी यूसीसी का समर्थन किया था। वहीं मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इसके बाद कहा कि अगर केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करती है तो इसका असर केवल मुसलमानों पर नहीं बल्कि सभी समुदायों पर पड़ेगा।

केदारनाथ धाम के लिए यात्रा फिर शुरु, 17 घंटे के बाद खुला बद्रीनाथ हाइवे

देहरादून । केदारनाथ धाम के क्षेत्रों में बारिश होने के चलते रोकी गई यात्रा फिर शुरू कर दी गई। केदारनाथ धाम व पैदल मार्ग पर बारिश कम होने पर यात्रियों को सोनप्रयाग से छोड़ दिया गया। इसके पहले सुबह दस बजे बारिश तेज होने पर सोनप्रयाग व गौरीकुंड में लगभग 1500 यात्रियों को रोका गया था, बारिश कम होने पर सभी यात्रियों को लगभग 12 बजे फिर से केदारनाथ जाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं केदारनाथ हाईवे सुबह अवरुद्ध होने के कारण यातायात के लिए खोल दिया गया था। छिनका में 17 घंटे तक अवरुद्ध रहा बदरीनाथ हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन यहां पहाड़ी से पत्थर गिरने जारी हैं। रातभर हाईवे को खोलने का काम जारी रहा। जिसके बाद शुक्रवार को तड़के 3 बजकर 30 मिनट पर हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने सबसे पहले पीलकोटी व बिरही की ओर फंसे यात्रा वाहनों को गंतव्य की ओर भेजा गया, बाद में चमोली की ओर फंसे वाहनों को भेजा गया। हाईवे खुलने पर तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और सेना के जवानों ने राहत की सांस ली है। हाइवे खुलने के साथ वन-वे में वाहनों की आवाजाही की जा रही है।

भारत के लिए एमक्यू-9बी ड्रोन के वास्ते प्रस्तावित लागत 27 प्रतिशत कम, बातचीत शुरू होनी बाकी: सूत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि भारत के लिए एमक्यू-9बी ड्रोन के वास्ते अमेरिका द्वारा प्रस्तावित औसत अनुमानित लागत वाशिंगटन से इसे खरीदने वाले अन्य देशों की तुलना में 27 प्रतिशत कम होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि बातचीत के दौरान इसे और कम करने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि अभी तक मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। अधिकारी ने विश्वास व्यक्त किया कि अंतिम कीमत अन्य देशों द्वारा वहन की जाने वाली लागत की तुलना में प्रतिस्पर्धी होगी। अधिकारी ने कहा कि कीमतें तभी बढ़ाई जा सकती हैं जब भारत इन ड्रोन में अतिरिक्त विशिष्टताओं की मांग करेगा। संबंधित 31 ड्रोन की प्रस्तावित खरीद की दिशा में नवीनतम आधिकारिक घटनाक्रम रक्षा खरीद परिषद द्वारा दी गई आवश्यकता की स्वीकृति का रहा है, जो 15 जून को हुआ था। अमेरिका निर्मित इन ड्रोन की सांकेतिक लागत 307.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।

अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक ड्रोन के लिए यह कीमत 9.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर बैठती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस ड्रोन को रखने वाले कुछ देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात को प्रति ड्रोन 16.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत जिस एमक्यू-9बी को खरीदना चाहता है, वह संयुक्त अरब अमीरात के बराबर है, लेकिन बेहतर संरचना के साथ है। अधिकारी के अनुसार, ब्रिटेन द्वारा खरीदे गए ऐसे 16 ड्रोन में से प्रत्येक की कीमत 6.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन यह सेंसर, हथियार और प्रमाणन के बिना केवल एक हरित विमान था। सेंसर, हथियार और पेलोड जैसी सुविधाओं पर कुल लागत का 60-70 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है। उन्होंने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि भारत के सौदे के आकार और इस तथ्य के कारण कि विनिर्माता ने अपने शुरुआती निवेश का एक बड़ा हिस्सा पहले के सौदों से वसूल कर लिया है, नयी दिल्ली के लिए कीमत दूसरे देशों की तुलना में कम हो रही है।

हालाँकि, उन्होंने कहा कि भारत को इन ड्रोन के साथ अपने कुछ रडार और मिसाइलों को एकीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कीमत में संशोधन हो सकता है। यह टिप्पणी कांग्रेस द्वारा करोड़ों रुपये के भारत-अमेरिका ड्रोन सौदे में पूर्ण पारदर्शिता की मांग किए जाने के एक दिन बाद आई है, जिसने आरोप लगाया कि 31 एमक्यू-9बी प्रीडेटर ड्रोन अधिक कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि ऐसा बयान शायद अज्ञानता के कारण दिया गया होगा। इन खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि वायुसेना ने ड्रोन के बारे में कुछ सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि रक्षा बलों के ये सभी अंग परामर्श के दौरान अपनी बात रखेंगे। हालांकि, वायुसेना, थलसेना और नौसेना ने सभी स्तरों पर इनकी खरीद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के हिस्से के रूप में 15-20 प्रतिशत तकनीकी जानकारी चाहता है और इंजन, रडार प्रोसेसर इकाइयों, वैमानिकी, सेंसर और सॉफ्टवेयर सहित प्रमुख घटकों एवं उपप्रणालियों का निर्माण और स्रोत यहीं से किया जाएगा।सूत्रों ने कहा कि एक बार दोनों सरकारों से सौदे को अंतिम मंजूरी मिल जाने के बाद, भारत अपनी तत्काल जरूरतों

को पूरा करने के लिए इनमें से 11 ड्रोन जल्द खरीदने पर विचार कर रहा है और बाकी को देश में ही तैयार किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि झूठी खबरें और प्रचार करके सौदे को बाधित करने का प्रयास किया जा सकता है क्योंकि उन्नत हथियारों से भारत के प्रतिद्वंद्वियों में डर और घबराहट पैदा होगी तथा इन उन्नत ड्रोन से भारत को अपने दुश्मनों पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने में मदद मिलेगी।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

महिला अधिकारियों की मांग को मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (एनसीसीएसए) की दूसरी बैठक हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित था।

बैठक में तीन मुद्दे रखे गए, जिसमें से एक पर सहमति बन पाई। बैठक में शिक्षा विभाग में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रोक दिया क्योंकि उनके खिलाफ विजिलेंस के केस चल रहे हैं।इसके अलावे शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को विभाग से हटाने का प्रस्ताव था, उस पर भी मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई और प्रस्ताव को रोक दिया गया। वहीं कुछ महिला अधिकारियों ने निजी कारणों से सब रजिस्ट्रार की पोस्टिंग से हटाने की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए स्वीकृति प्रदान कर दी। एनसीसीएसए की यह बैठक मुख्यमंत्री निवास स्थित कैंप कार्यालय में हुई। दिल्ली सरकार में सर्विसेज को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश में मुख्यमंत्री केजरीवाल को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधी सेवा विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव में तीन अलग-अलग श्रेणी के अनुरोध शामिल था। इसके अलावा इसमें कुछ निजी तौर पर अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की मांग को लेकर किए गए अनुरोध शामिल था। इसमें आज हुई बैठक में दो पर सहमति नहीं बन पाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एनसीसीएसए की बैठक में सदस्य सचिव एवं मुख्य सचिव शामिल हैं। इस अथॉरिटी के तीन सदस्यों में कोई भी फैसला 2-1 से पास होता है। जिस मुद्दे पर दो सदस्य सहमत होते हैं, वह स्वीकृत हो जाता है।

गश्त कर रहे पुलिस के दो जवानों पर सर्जिकल ब्लेड से हमला, हमलावर गिरफ्तार

नई दिल्ली। पश्चिम दिल्ली के मायापुरी इलाके में गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के दो जवानों पर बदमाशों ने सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया। हालांकि घायल होने के बाद भी जवानों ने हमलावरों को नहीं छोड़ा।

दोनों ही हमलावर सगे भाई हैं। इनकी पहचान विशाल उर्फ डीसी (26) और कृष्ण (28) के रूप में हुई है, जो आपस में भाई हैं। विशाल मायापुरी थाने का घोषित बदमाश है। इसके खिलाफ छह और कृष्ण के खिलाफ एक मामला पहले से दर्ज है। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल एक सर्जिकल ब्लेड और एक चाकू बरामद हुआ है। बाद में जख्मी हालत में हवलदार विक्रांत को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा और ड्यूटी के दौरान हमला करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हवलदार विक्रांत और सिपाही हरीश दोनों मायापुरी थाने में तैनात हैं। मंगलवार रात के समय दोनों एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस बीच दोनों रेवाड़ी लाइन झुग्गियों के पास पहुंचे। इस दौरान दोनों घोषित बदमाशों की जांच करने लगे। अचानक विशाल नामक बदमाश ने विक्रांत के गले पर सर्जिकल ब्लेड से हमले का प्रयास किया। समय रहते विक्रांत ने हाथ अड़ाकर वार को रोक दिया। हमले में उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद भी उसने विक्रांत को नहीं छोड़ा। उसी समय विशाल का बड़ा भाई कृष्ण भी वहां पहुंच गया। उसने भी विक्रांत व हरीश पर हमले का प्रयास किया। हालांकि पुलिस जवानों ने उसे भी काबू कर लिया गया। बाद में दोनों को थाने ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीसीआर की मदद से फौरन विक्रांत को नजदीकी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस की टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की छानबीन कर रही है।

दिल्ली मेट्रो बना जंग का मैदान, दो यात्रियों में हुई मारपीट

नई दिल्ली। इन दिनों राजधानी दिल्ली की लाइफ लाइन माने जाने वाली दिल्ली मेट्रो वायरल वीडियो को लेकर खासी चर्चा में बनी हुई है। आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बंटोर रहा है। इसी क्रम में अब एक ऐसा वीडियो आया है, जिसमें दो यात्री एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसमें दो यात्री बीच बचाव भी करते देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो वायलेट लाइन का है, जो कश्मीरी गेट और राजा नाहर सिंह के बीच चलती है। दोनों के बीच खूब मारपीट हुई है। इसमें सुनाई दे रहा है कि अन्य यात्री लड़ाई करने वालों को बाहर निकलने को कह रहे हैं। डीएमआरसी का कहना है कि ऐसी हरकतों के लिए मेट्रो जिम्मेदार नहीं है। इसको लेकर यात्रियों को खुद सतर्क सावधान होने की जरूरत है। अगर कोई यात्री दूसरे यात्री की शिकायत करता है, तो उस पर डीएमआरसी कानूनी प्रक्रिया अपनाती है। वहीं, वीडियो से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि डीएमआरसी मेट्रो में बार-बार घोषणा करती है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना मना है। इसके बावजूद लोग वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बजाए अगर वह इसकी शिकायत डीएमआरसी से करेंगे, तो आरोपी यात्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

एनडीएमसी ने अपने क्षेत्र में एक जुलाई से 30 सितंबर तक सड़कों की कटाई और खुदाई पर लगाई रोक

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने मानसून के मौसम को देखते हुए सड़क काटने और खोदने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध 01 जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। यह प्रतिबंध आपातकालीन स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर किये जाने वाले कार्यों पर लागू नहीं होगा तथा इसके अतिरिक्त सभी शेष अन्य कार्यों पर लागू रहेगा ।

एनडीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार, एनडीएमसी ने यह भी निर्णय लिया है कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसी भी सड़क की कटाई जो पहले से ही चल रही है, उस स्थान को साफ-सुथरा, समतल और अच्छी तरह से बहाल किया जाएगा। किसी भी मामले में, जहां पालिका परिषद क्षेत्र के लिए सड़क काटने या खोदने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन जमीन पर कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वहां भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से आपातकालीन कार्य को छोड़कर, सड़क काटने या खोदने की प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी सड़क कटाई या खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एनडीएमसी हर महीने के शुरुआती शनिवार को सुविधा शिविर लगाएगी

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) आने वाले दिनों में हर महीने के शुरुआती शनिवार को नागरिकों की सुविधा के लिए सुविधा कैंप का आयोजन करेगी। इस दौरान शिकायत निवारण सुविधा कैंप में विभिन्न विभागों के हेल्प डेस्क सेवा उपयोगकर्ताओं, कर्मचारियों, आरडब्ल्यूए, एमटीए और एनडीएमसी के निवासियों की शिकायतों का निवारण और सुविधा प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

एनडीएमसी के विभिन्न विभाग इस सुविधा कैंप के हिस्सा होंगे, उसमें प्रमुख रूप से सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,सार्वजनिक स्वास्थ्य, वास्तुकार और पर्यावरण, वाणिज्यिक, स्वास्थ्य लाइसेंसिंग, एस्टेट-द्व, एस्टेट-द्वद्व, बागवानी-उत्तर, बागवानी-दक्षिण, संपत्ति कर, शिक्षा, अग्नि, लेखा, वित्त, पेंशन, प्रवर्तन-उत्तर, प्रवर्तन-दक्षिण, कार्मिक विभाग, कल्याण विभाग, चिकित्सा सेवाएं, पार्किंग प्रबंधन प्रणाली, मुख्य सुरक्षा कार्यालय, ईबीआर विभाग, म्युनिसिपल हाउसिंग, लाइब्रेरी, सतर्कता और आईटी विभाग सम्मिलित हैं।

इन शिकायतों का होगा निवारण:

सुविधा कैंप में नए बिजली कनेक्शन/डिस्कनेक्शन, लोड वृद्धि/कमी, नाम परिवर्तन/स्थानांतरण, संपत्ति कर, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, एनडीएमसी के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा मामलों, जल भराव, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान, सड़क मरम्मत, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, बरात घर और पार्कों की बुकिंग और एनडीएमसी द्वारा दी जाने वाली कई अन्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एनडीएमसी हर महीने के पहले शनिवार को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, जय सिंह रोड पर सुविधा शिविर का आयोजन कर रही है। इन सुविधा शिविरों के आयोजन के अलावा पालिका परिषद ने एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों के लिए संपर्क रहित शिकायत निवारण तंत्र के रूप में एक जन सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया है।

इस जन सुविधा पोर्टल का लिंक एनडीएमसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पोर्टल का उपयोग शिकायत दर्ज करने, उस शिकायत की स्थिति पर नज़र रखने और शिकायत निवारण तंत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए किया जा सकता है।

दिल्ली- मंगोलपुरी हत्याकांड में भगोड़ा घोषित शहजाद मेवात से गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले साल मंगोलपुरी में हुए खूनी संघर्ष के आरोपित शहजाद को मेवात के पिनगवां से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 8 आरोपितों और तीन नाबालिग को पहले ही पकड़ लिया था लेकिन शहजाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। कोर्ट द्वारा उसे भगोड़ा घोषित किया गया था और दिल्ली पुलिस ने उस पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

शहजाद ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह ग्रेजुएट डिग्रीधारक है। वह मंगोलपुरी के के-ब्लॉक में साइबर कैफे का कार्य कर रहा था। फरार होने के बाद वह लगातार भीड़भाड़ वाली कालोनियों में अपना ठिकाना बदलता रहा। आखिरी दौर में वह मेवात जिले में रह रहा था। वहीं से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष सितंबर महीने में फरदीन नामक युवक दिल्ली के मंगोलपुरी में एक भीड़ भरी सड़क से गुजर रहा था। उस दौरान गलती से उसका हाथ करण और बादशाह को लग गया, जो अपने दोस्तों समीर, मुथु, शाहबीर, शाहरुख और अन्य के साथ वहां खड़ा था। कुछ समय बाद फरदीन वहां से चला गया। मामले को सुलझाने के लिए वह अपने भाई नईम के कहने पर अरमान के साथ वापस आया लेकिन करण, बादशाह और उसके दोस्तों ने फरदीन और उसके भाइयों को गाली देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया और मारपीट होने लगी। करण, बादशाह के दोस्तों ने फरदीन और उसके भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया।सभी घायलों को मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां अरमान ने दम तोड़ दिया। घायल फरदीन के बयान पर प्राथमिकी संख्या 1044/22, धारा 302/307/147/148/149/34 भारतीय दण्ड संहिता और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत थाना मंगोलपुरी में दर्ज की गई।

रोहिणी में जापानी पार्क के पास मिला किन्नर का शव, केजरीवाल ने सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले में जैपनीस पार्क के पास एक किन्नर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सुबह चार बजे के करीब सूचना मिली कि जापानी पार्क के पास मेन रोड के किनारे एक शव देखा गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि वह किन्नर है और उसके पेट और सीने पर चाकू मारकर हत्या की गई है। प्रशांत विहार थाना पुलिस और क्राइम टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। देखने से अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतक की उम्र 25 साल के आसपास की है, जिसको मारने के बाद शव को यहां जैपनीस पार्क के पास फेंका गया है।

पुलिस लगातार जिस जगह पर बॉडी मिली थी उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान भी की गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ अब इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आ गया है। उन्होंने सुरक्षा-व्यवस्था का हवाला देते हुए ट्वीट किया, पूरी दिल्ली में लोगों में इस तरह डर का माहौल है। पर इनके पास दिल्ली वासियों को सुरक्षा देने के लिए ना समय है, ना नीयत है और ना कोई प्लान। आखिर लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे।? फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले में आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर की गई है।

दिल्ली जल बोर्ड ने परियोजनाओं के लिए कानूनी फर्म की नियुक्ति को लेकर पारित किया आदेश

नई दिल्ली,। केजरीवाल सरकार दिल्ली में हर घर को साफ और भरपूर पानी उपलब्ध कराने और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए अनधिकृत कालोनियों व गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इस क्रम में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 1500 से अधिक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर जल मंत्री सौरभ भारद्वाज की अध्यक्षता में दिल्ली जल बोर्ड ने आदेश पारित किया है कि डीजेबी की 10 करोड़ से ऊपर की सभी नई परियोजनाओं में अलग-अलग एक्सपर्ट कानूनी फर्म को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। परियोजना से जुड़े सभी कानूनी अनुपालन, कम्युनिकेशन और कांट्रेक्ट एग्रीमेंट के कार्य कानूनी फर्म करेगी। इससे जहां कंपनी द्वारा एग्रीमेंट के उल्लंघन पर डीजेबी द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी, वहीं कानूनी फर्म यह भी सुनिश्चित करेगी कि जनता के लिए शुरू की जाने वाली परियोजनाएं उच्च गुणवत्ता और सभी कानूनों का पालन करते हुए पूरी हो सके, ताकि जनता को इनका लाभ मिले। दिल्ली सरकार के अनुसार केजरीवाल के निर्देशों का पालन करते हुए डीजेबी द्वारा यमुना को प्रदूषण मुक्त करने और दिल्ली में 24 घंटे जलापूर्ति प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए 1500 से अधिक परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। केजरीवाल प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी स्वयं कर रहे हैं। जल मंत्री व डीजेबी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज द्वारा हर सप्ताह सभी परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। परियोजनाओं की समीक्षा करते समय यह देखा गया कि लोगों के हित वाली कई परियोजनाओं में कानूनी तौर पर एग्रीमेंट से विचलन (डेविएशन) है। यह भी पता चला कि ऐसी भी कई परियोजनाएं है, जोकि विभिन्न कारणों से अदालतों में या अन्य कानूनी कारणों के चलते लटकी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी फैली हुई है।

अध्यादेश पर पहले ही केंद्र को घेर चुके हैं केजरीवाल

नई दिल्ली। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कैंपेन के अगले चरण की घोषणा कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश की प्रतियां जलाने का फैसला किया है। तीन जुलाई को आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां जलाएगी। वहीं, आम आदमी पार्टी ने पांच जुलाई को सभी विधानसभाओं में और छह से 13 जुलाई तक हर गली-मोहल्ले-चौके पर अध्यादेश की प्रतियां जलाने का फैसला किया है। रामलीला मैदान में हुई महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों के वोट का अपमान किया। पूरा देश दिल्ली वालों के साथ। 140 करोड़ लोग मिलकर संविधान बचाएंगे। अंदर से पता चला है, जैसे दिल्ली में तानाशाही लागू हई, कल इसी तरह बंगाल और राजस्थान के लिए भी लाया जाएगा। चौथी पास राजा को समझ नहीं आ रहा है कि देश कैसे चलाया जाए। चारों तरफ

सीएम केजरीवाल ने सीधे तौर पर भाजपा पर नौकरशाही के जरिये दिल्ली की सरकार चलाने का षडयंत्र रचने का आरोप लगाया था। केंद्र को घेरते हुए सीएम ने कहा था कि दिल्ली में अब चुनी हुई सरकार की नहीं, अफसरों की चलेगी। देश के इतिहास में यह पहली बार होगा। जब नौकरशाह चुनी हुई सरकार चलाएंगे।

काले अध्यादेश को हराना बहुत जरूरी

वहीं काले अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी डीजेबी को दी है। यमुना क्लीनिंग सेल नए एसटीपी, डीएसटीपी का निर्माण, मौजूदा

इसे लेकर जल मंत्री सौरभ भारद्वाज की अध्यक्षता में दिल्ली जल बोर्ड ने आदेश पारित किया है कि डीजेबी की 10 करोड़ से ऊपर की सभी नई परियोजनाओं में अलग-अलग एक्सपर्ट कानूनी फर्म को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा।

एसटीपी का 10/10 तक उन्नयन और क्षमता वृद्धि, अनधिकृत कालोनियों में सीवरेज नेटवर्क बिछाना, सेप्टेज प्रबंधन; ट्रंक/परिधीय सीवर लाइनों की गाद निकालना, पहले से अधिसूचित क्षेत्रों में सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना, आइएसपी के तहत नालों की ट्रैपिंग, नालियों का इन-सीटू ट्रीटमेंट आदि कार्य कर रही हैं, ताकि दिल्लीवालों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले।

दिल्ली सरकार के वित्तपोषित कॉलेजों के लिए 100 करोड़ जारी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने वित्तपोषित 12 कॉलेज के लिए दूसरी तिमाही में 100 करोड़ रूपये जारी किए हैं। बुधवार को एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने साझा किया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के आने के बाद से इन कॉलेजों को दिए जाने वाले बजट में 3 गुणा से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है जो शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आतिशी ने कहा कि, दिल्ली सरकार के लिए शिक्षा हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के साथ-साथ अरविन्द केजरीवाल सरकार ने उच्च शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया और तीन नई यूनिवर्सिटी खोलीं, मौजूदा यूनिवर्सिटीज का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की उच्च शिक्षा में दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित 12 दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उन्होंने बताया कि, दिल्ली सरकार ने इन कॉलेजों को दिए जाने वाले

फंड में पिछले 8 साल में 3 गुणा का इजाफा हुआ है। 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रूपये आवंटित किये गए थे, आज 2023-24 में आवंटन की राशि 3 गुणा बढ़कर 400 करोड़ हो गई है। इन कॉलेजों में पिछले कुछ सालों से वित्तीय कुप्रबंधन के कई मुद्दे सामने आये लेकिन अरविन्द केजरीवाल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मैनेजमेंट के कारण, एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों की वजह से उन कॉलेजों के शिक्षकों और विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ कॉलेजों का ऑडिट चल रहा है फिर भी शिक्षकों की बेहतरी का ध्यान रखते हुए, उनके मेडिकल बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट्स जो वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से रुके हुए थे, इसका ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय के इन 12 कॉलेजों के लिए 100 करोड़ रूपये का फंड जारी कर रही है।उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रूपये का ग्रांट दिया गया था7 केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद से वर्ष 2015-16 में 147 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 156 करोड़ रुपये, वर्ष 2017-18 में 171 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 213 करोड़ रूपये,वर्ष 2019-20 में 235 करोड़ रूपये, वर्ष ,2020 -21 में 265 करोड़ रूपये , वर्ष 2021-22 में 308 करोड़ रूपये, वर्ष 2022-23 में 361 करोड़ रूपये और इस साल इन कॉलेजों को 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ 'आप' का अगला कदम, प्रतियां जलाकर करेगी विरोध

एनडीएमसी ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया है। पालिका परिषद के अध्यक्ष अमित यादव की अध्यक्षता में एनडीएमसी की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत 'औरंगजेब लेन' का नाम बदलकर 'डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम लेन' करने पर नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 231 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के संदर्भ में विचार करने के लिए परिषद के समक्ष एक एजेंडा रखा गया। परिषद ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लेन' करने को मंजूरी दे दी। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि औरंगजेब के नाम पर तो पहले ही यहां पर कोई सड़क नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब हमने बदलाव कर दिया है। जल्द औरंगजेब लेन का नाम बदल कर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम रखा जाएगा। औरंगजेब लेन को अब लोग एपीजे अब्दुल कलाम लेन के नाम से जानेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही गृह मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। भारत सरकार, डाक एवं तार विभाग, भारत सरकार राज नामकरण प्राधिकरण, दिल्ली सरकार और विभाग भी परिषद के कार्य वक्त की पुष्टि की प्रत्याशा में आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल ही केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर किया था। वहीं इस वर्ष जनवरी में राष्ट्रपति भवन के 'मुगल गार्डन' का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' कर दिया गया था।